मुंबई(महाराष्ट्र) से प्रकाशित

हिन्दी दैनिक

उत्तरशक्ति

हर खबर निष्पक्षता के साथ

मुंबई
वर्षः 7 अंक 266
गुरुवार, 17 अप्रैल 2025
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshaktinews.com

आरएसएस और भाजपा को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही हरा सकती हैः राहुल गांधी

गुजरात, 16 अप्रैल। गुजरात में राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही आरएसएस और भाजपा को हरा सकती है। राहुल ने मोडासा शहर में कांग्रेस कार्यकताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम राज्य में भाजपा को हराएंगे। उन्होंने कार्यकताओं में जोश भरते हुए कहा कि गुजरात कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। राहुल ने कहा कि मौजूदा लड़ाई सिर्फ. राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि बीजेपी-आरएसएस और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई भी है। पूरा देश जानता है कि अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है, तो वो सिर्फ. कांग्रेस पार्टी है। अगर हमें देश में आरएसएस और बीजेपी को हराना है, तो इसका रास्ता गुजरात से होकर जाता है।

कांग्रेस नेता कहा कि हमारी पार्टी की शुरूआत गुजरात से ही हुई थी। आपने हमें हमारे सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी और सरदार पटेल दिए। लेकिन गुजरात में हम लंबे समय से हतोत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके जिले के वरिष्ठ नेताओं से मिला, जिन्होंने मुझे बताया कि हमारे बीच की प्रतिस्पर्धा रचनात्मक नहीं, बल्कि विनाशकारी है। दूसरी बात, स्थानीय टिकट वितरण में स्थानीय लोगों को शामिल नहीं किया जाता। चर्चा का मुख्य बिंदु

यह था कि जिला अहमदाबाद से नहीं चलना चाहिए; जिला जिले से चलना चाहिए। जिले के नेताओं को मजबूत किया जाना चाहिए। जिला अध्यक्ष को जिम्मेदारी और शक्ति दी जानी चाहिए। हम यह काम अभी से शुरू कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि जिला अध्यक्ष कोई समझौतावादी उम्मीदवार नहीं होगा। वो आपकी मदद से जिला चलाएगा।

जिला उसके फैसलों से चलेगा। उम्मीदवार को ऊपर से निर्देश नहीं मिलेंगे। हम चाहते हैं कि संगठन और चुनाव लड़ने वालों के बीच एक जुड़ाव होना चाहिए। आजकल होता ये है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन लोगों को चुनाव जिताने में मदद करता है और एक बार कोई व्यक्ति विधायक या सांसद बन जाता है तो वो कांग्रेस संगठन को भूल जाता है। उन्होंने कहा कि गुजरात में ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है क्योंकि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि गुजरात हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है।

गांधी ने कहा कि हम उन लोगों को ताकत देना चाहते हैं जिनकी बूथ लेवल पर पकड़ है। हमें नई पीढ़ी को कांग्रेस पार्टी में लाना है जो लोग जनता से जुड़े हैं उन्हें आगे बढ़ाना है।

मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

मऊ, 16 अप्रैल। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की एक अदालत ने वर्ष 2020 के एक मामले के सिलसिले में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अदालत के अधिकारियों के अनुसार, अफसा अंसारी के दक्षिण टोला थाने में दर्ज मामले के सिलसिले में बार-बार समन के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने के लिए वारंट जारी किया गया। उन्होंने बताया, इस मामले में अफसा के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 299 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी गई है और उनका नाम अब मकरूल रजिस्टर में जोड़ा जा रहा है। मकरूल रजिस्टर उन फरार आरोपियों की सूची है जो

अदालती कार्यवाही से बचते हैं। अदालत ने धारा 82 और 83 सीआरपीसी (भारतीय दंड सहिता) के तहत कार्रवाई करते हुए अफसा को भगोड़ा अपराधी घोषित किया था और उनकी संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया था। पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर) अंजनी कुमार पांडे ने बताया, अफसा अंसारी को पहले ही वांछित घोषित किया जा चुका था और उस पर इनाम रखा गया था, जिसे अब बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि अदालत के आदेश के बाद अफसा का नाम मकरूल रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है और कानूनी कार्रवाई जारी है। अधिकारियों ने बताया कि अफसा अंसारी ने अब तक मामले में अपना बयान दर्ज नहीं कराया है, जिस वजह से अदालत ने उसकी गिरफ्तारी के लिए स्थायी वारंट जारी किया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 अप्रैल से लखनऊ के तीन दिवसीय दौरे पर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे और अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। एक पदाधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवाररात पौने नौ बजे लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरेंगे, जहां से वह सीधे 5ए कालिदास मार्ग अपने सरकारी आवास पर जाएंगे। उन्होंने बताया कि सिंह 19 अप्रैल यानी शनिवार को सुबह साढ़े नौ बजे के.डी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ की शुरूआत करेंगे। द्विवेदी ने बताया कि इस कार्यक्रम के बाद वह पूर्वाह्न 11 बजे मुन्नू खेड़ा सदरौना रोड जाएंगे और पश्चिम मंडल3 के वरिष्ठ कार्यकताओं के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री अगले दिन रविवार को पूर्वाह्न 11 बजे आईआईएम रोड स्थित महर्षि डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे और वहां उत्तर मंडल4 वरिष्ठ कार्यकताओं के साथ संवाद करेंगे। महानगर अध्यक्ष ने बताया कि सिंह दोपहर सवा 12 बजे अलीगंज में डॉ. बिंदेश्वर पाठक की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे।

दिल्ली सरकार ने ईवी नीति को तीन महीने बढ़ाया, बिजली सब्सिडी जारी रहेगी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को तीन महीने के लिए बढ़ाने और राष्ट्रीय राजधानी में बिजली सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चार श्रेणियों के लिए मौजूदा बिजली सब्सिडी जारी रखने को भी मंजूरी दी गई।

ये चार श्रेणियां हैं- घरेलू उपभोक्ता, किसान, चैंबर वाले वकील और वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित। बाद में दिल्ली सचिवालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि तिपहिया या किसी अन्य श्रेणी के वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

सरकार अपने निवासियों के लिए कई चीजें करना चाहती है, और हम उन्हें संशोधित ईवी नीति में शामिल करेंगे। हालांकि, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि तिपहिया पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, न ही किसी भी श्रेणी के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है।

आरएसएस नेता की हत्या के मामले में पीएफआई सदस्यों की जमानत के खिलाफ दायर एनआईए की याचिका खारिज

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय ने 2022 में केरल के पलक्कड़ में आरएसएस के नेता श्रीनिवासन की हत्या से जुड़े मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 17 सदस्यों को जमानत दिए जाने के खिलाफ दायर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की याचिकाओं पर विचार करने से बुधवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह ने कहा कि आरोपियों को जमानत दिए जाने का केरल उच्च न्यायालय का आदेश डेढ़ साल पुराना है और उच्च न्यायालय के पास शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द

करने की शक्ति है।

पीठ ने कहा, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि याचिकाकताओं को जमानत के खिलाफ विशेष अदालत में आवेदन करने की स्वतंत्रता है। इसलिए, याचिकाकर्ता इन याचिकाओं में दिए गए आधारों पर जमानत रद्द कराने के लिए कभी भी विशेष अदालत में आवेदन कर सकते हैं।

वास्तव में विशेष अदालत अधिक उपयुक्त अदालत होगी। पीठ ने कहा, इसलिए, इस स्तर पर हम विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर रहे हैं और याचिकाकताओं को जमानत के खिलाफ विशेष अदालत/उच्च न्यायालय का रुख करने की स्वतंत्रता देते हैं।

केरल उच्च न्यायालय ने 25 जून, 2024 को पीएफआई के 17 आरोपी सदस्यों को जमानत दे दी थी। 26 आरोपियों में से 17 को जमानत देते हुए उच्च न्यायालय ने कड़ी शर्तें लगाई थीं, जिनमें जांच अधिकारी से मोबाइल फोन नंबर और जीपीएस लोकेशन साझा करना शामिल है।

जस्टिस बीआर गवई होंगे देश के नए मुख्य न्यायाधीश

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने आधिकारिक तौर पर न्यायमूर्ति बीआर गवई को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की है, तथा उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया है। इस सिफारिश से न्यायमूर्ति गवई के भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ऐसे में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे, जो कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद होगा।

परंपरा के अनुसार, मुख्य

न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित करते हुए केंद्रीय विधि मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। मंत्रालय ने पहले मुख्य न्यायाधीश से उनके उत्तराधिकारी के नाम का प्रस्ताव मांगा था। न्यायमूर्ति गवई लगभग छह महीने तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे क्योंकि वे नवंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन के बाद वे मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाले दूसरे दलित होंगे, जिन्हें 2007 में देश के शीर्ष न्यायिक पद पर पदोन्नत किया गया था।

महाराष्ट्र के अमरावती से आने वाले, वे 1985 में बार में शामिल हुए और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के पूर्व महाधिवक्ता और न्यायाधीश बैरिस्टर राजा भोंसले के साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने 1987 से 1990 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस की।

इसके बाद, उन्होंने मुख्य रूप से संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून से संबंधित मामलों में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के समक्ष वकालत की। अगस्त 1992 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त सरकारी वकील नियुक्त किया गया। उन्हें 2000 में नागपुर बेंच के लिए सरकारी वकील और सरकारी वकील नियुक्त किया गया।

कांग्रेस ने बाबा साहेब को धोखा दिया, भारत रत्न देने से मना किया: योगी आदित्यनाथ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह अपने राजनीतिक लाभ के लिए डॉ. बी.आर. आंबेडकर के विचारों को अपनाने का नाटक कर रही है और उनकी विरासत का व्यवस्थागत तरीके से अपमान कर रही है। मुख्यमंत्री ने यहां एक सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ के लिए संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने हर महत्वपूर्ण मौके पर बाबा साहेब को दरकिनार करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, 1952 और 1954 के उप चुनावों में बाबा साहेब को

किसने हराया। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में उनके शामिल होने का किसने विरोध किया। यह कांग्रेस ही थी। आदित्यनाथ ने कहा, बाबा साहेब के पूरे जीवनकाल में उनका अपमान करने वाली पार्टी अब अपने हाथों में संविधान लेकर लोगों को भ्रमित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर संविधान की प्रस्तावना में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए इसे संविधान की आत्मा पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा, जिस तरह से शरीर के लिए आत्मा आवश्यक है, उसी तरह संविधान के लिए प्रस्तावना का महत्व है। इस पार्टी द्वारा आपातकाल थोपकर संविधान का गला घोंटा गया। उन्होंने कांग्रेस पर दिल्ली में आंबेडकर का स्मारक बनाने से दशकों तक इनकार करने और उन्हें भारत रत्न नहीं देने का भी आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जहां कांग्रेस के परिवारों को 50 एकड़ का स्मारक उपहार में दे दिया गया, दिल्ली में बाबा साहेब के लिए एक इंच भी जमीन नहीं दी गई।

अरुणोदय सर्जिकल एण्ड ट्रामा सेन्टर
ARUNODAYA Surgical & Trauma Center

डा. अरूण आर. सिंह
कन्सल्टेन्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जन
एस.एम.ओ.) एल.टी.एम.एम. जी. एच. (सायन हॉस्पिटल मुम्बई)
स.आर.) एम. जी.एम. मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल (नवी मुम्बई)
रजि.नं.-82945 (यू.पी.एम.सी.)

जनरल सर्जरी
स्त्री एवं प्रसूति रोग
आर्थोपेडिक (सर्जरी एवं परामर्श)
कीमोथिरैपी सुविधा उपलब्ध
न्यूरो सर्जरी (परामर्श एवं सर्जरी)
वेन्टिलेटर एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध
प्रशिक्षित डाक्टर स्टाफ तथा सभी मानकों पर खरा उतरने वाला जनपद का एक मात्र हास्पिटल
दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार की सर्जरी
जनरल मेडिसिन, मधुमेह रोग
गुर्या एवं मूत्र रोग (सर्जरी एवं परामर्श)
गैस्ट्रोइन्टरोलॉजी (इण्डोस्कोपी एवं कालोनोस्कोपी)
एक्सीडेण्टल एवं ट्रामा इमरजेन्सी
सेवा 24 घण्टे उपलब्ध

डा0 पुनीत सिंह
M.S.M.C.H.
गुर्दा एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ (यूरो सर्जन)
डा0 रवि प्रकाश सिंह
M.S. (Ortho)
हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ
डा0 प्रभात सिंह
M.D.(Medicine)
कंसल्टेंट फिजिशियन
डा0 सुमित कुमार सिंह
M.D.(Neuro Psychiatrist)
मानसिक रोग विशेषज्ञ
24/7 Emergency Services

बीमा कार्ड धारकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध
Medi Assist STAR
आयुष्मान कार्ड द्वारा निःशुल्क इलाज की सुविधाएं
8090966086,8090015086
कलीचाबाद,जौनपुर

जरूरतमंद सीनियर सिटिजन के बेहतर देख-भाल हेतु समर्पित संस्था
YASHOJYOTI FOUNDATION'S
(MAHA/1211/2013/THANE)
ज्योति ओल्ड एज होम
JYOTI OLD AGE HOME
WE SERVICE FOR HUMANITY
Home For Aged, Senior Citizans, Pentioners Paralysis,
• Diabetic, Bed Ridden Patients.,• Paralysis, Alzheimer's dementia, post operative, palliative care schizophrenia, Treatement if needed., • Food Will Be Served Breakfast Lunch, Supple Dinner. (Veg & Non Veg), • Entertainment: Tv, Tape, News Paper, Indoor Games, Ample Place For Walking, Yoga., • 24x7 Ward Boy, Aaya, Atendant To Take Care., • Doctor's visit every day., • Specialist (Psyciaric, Dentist, Cardiologyst, physcian) visit on c, • Ambulance service on call., •

Dr. Jyoti MD (AM)
CONTACT NO.- 9820674896/9664682587
Padmakar Mhatre Hospital, Opp. Kakad Paradise, Penkar Pada, Mira Road (E), Thane - 401 107.

तमिलनाडु में भाजपा परचम फहराने को तत्पर

-ललित गर्ग

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही है, लेकिन अब भाजपा दक्षिण में अपनी जड़ों को न केवल मजबूत करना चाहती है बल्कि दक्षिण के राज्यों में सत्ता पर काबिज भी होना चाहती है। तमिलनाडु में अगले वर्ष अप्रैल-2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) ने 2026 के विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को अपनी महत्वपूर्ण चैन्नई यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अहम राजनीतिक गठबंधन का ऐलान करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य में एनडीए एडप्पादी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही गठबंधन का चेहरा होंगे। तमिलनाडु की भाजपा में भी एक बड़ा बदलाव सामने आया है और भाजपा की तमिलनाडु इकाई की कमान नैनार नागेंद्रन को मिल गई है। भाजपा की राजनीतिक यात्रा में 2026 का तमिलनाडु चुनाव मील का पत्थर साबित होगा, वर्षों की प्यास को बुझायेगा, कमल खिलायेगा।

यह बात तो जगजाहिर है कि दक्षिण में हिन्दू मन्दिरों एवं संस्कृति का वर्चस्व होते हुए भी भाजपा अब तक अपनी जमीन मजबूत नहीं कर पाई है, जबकि केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु हो, भाजपा अपनी जड़ों को सुदृढ़ करने की जद्दोजहद करती रही है। भाजपा के प्रयास दक्षिण में बेअसर ही रहे हो, ऐसी बात भी नहीं है, समय-समय पर उसके प्रयास रंग लाते रहे हैं। दक्षिण के चार में से तीन राज्यों में भाजपा अपना प्रभाव और प्रभुत्व दिखा चुकी है। कर्नाटक में कई बार भाजपा सत्ता आसीन हो चुकी है, आंध्र प्रदेश में इस समय सत्ता की भागीदार है, तेलंगाना में भी भाजपा मजबूत पकड़ बना चुकी है, केवल तमिलनाडु ही है जहां भाजपा कई दशकों से उपस्थिति दर्ज कराने के बावजूद सत्ता तक नहीं पहुंच पायी है। मोदी के प्रभाव और भाजपा के विशाल संसाधनों के बावजूद तमिलनाडू जीतना उसके लिए मुश्किल रहा है। पिछले 78 सालों में यहां कभी भी भाजपा-संघ की राष्ट्रवादी विचारधारा या हिंदुत्व के उनके संस्करण को स्वीकार नहीं किया है। यह सिर्फ भाजपा के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक बड़ी वैचारिक लड़ाई है। लेकिन इस बार भाजपा की रणनीति एवं तैयारियों एवं मोदी-शाह के संकल्पों एवं इरादों में दम है, तमिलनाडु में आमूल-चूल परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। तमिलनाडु में भाजपा की राजनीतिक रणनीति में किये गये बदलाव एवं रणनीतियां एक बड़ा मोड़ है, एक नया उजाला है। राजनीति के चाणक्य अमित शाह का यह भरोसा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगा और राज्य में सरकार बनाएगा, कोरी हवा में उछाली गयी बात नहीं है।

एआईडीएमके और भाजपा के बीच गठबंधन 1998 से बनते-बिगड़ते रहे हैं। 1998 की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनाने और फिर 13 महीने बाद उसे गिराने का श्रेय भी एआईडीएमके को जाता है। जे. जयललिता का जब तक जीवनकाल रहा तब तक भाजपा नेतृत्व के साथ एआईडीएमके की नजदीकियां बनी रही। जब 1999 में जयललिता ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया तो करुणानिधि ने डीएमके को भाजपा के साथ जोड़ लिया और 2004 तक सत्ता का सुख लेते रहे। 2004 के आम चुनाव में फिर से एआईडीएमके भाजपा के साथ आई लेकिन तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें नहीं जीत सकी। लेकिन मोदी-शाह की नजरें हमेशा इस राज्य पर लगी रही। क्योंकि सामरिक रूप से तमिलनाडु एक संवेदनशील राज्य है, श्रीलंका के साथ उसका सीधा जुड़ाव है। चीन श्रीलंका के माध्यम से भारत में पैठ बनाना चाहता है, ऐसे में तमिलनाडु में केंद्र की आंख बंद कर विरोध करने वाली पार्टी का सत्तासीन रहना देश हित के लिए गंभीर सवाल पैदा करता है, अनेक संकटों का कारण बन सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपने तीसरे कार्यकाल की बड़ी चुनौतियों में बंगाल, तमिलनाडु, केरल को जीतना है। वैसे इन राज्यों में भाजपा की जीत एक करिश्मा ही होगा, लेकिन मोदी-शाह ऐसे आश्चर्यकारी करिश्में घटित करते रहे हैं। सर्वविदित है कि भाजपा के लिए तमिलनाडु केवल राजनीतिक संघर्ष का मैदान नहीं है, वैचारिक लड़ाई भी लड़ी जानी है। स्टालिन सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विवादित करने और त्रिभाषा सिद्धांत को हिंदी थोपने की कोशिश के रूप में प्रचारित करने से केंद्र आहत है, इसीलिये भाजपा अपने राजनीतिक सिद्धांतों, योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नीतियों को गंभीर चुनौती दे रहे इन नेताओं और दलों को वैचारिक धरातल पर परास्त करने का रास्ता भी खोज रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्राओं एवं अन्य चचाओं में यह बताते रहे हैं कि पूरे तमिलनाडु की जनता एवं राज्य उनके दिल में हैं, वे उसके कल्याण एवं विकास के लिये तत्पर है। तमिल लोगों के दिलों को जीतने का काम अकेले भाजपा के द्वारा संभव नहीं है, इसीलिये एआईडीएमके की बैशाखियां उसके लिये जरूरी है। भाजपा के राजनीतिक समीकरणों की सार्थक निष्पत्ति का एक हिस्सा है एआईडीएमके और भाजपा के ताजा गठबंधन की घोषणा। इस गठबंधन को सहज बनाने और पार्टी के अनुरूप इसका स्वरूप देने का श्रेय गृहमंत्री अमित शाह को जाता है, क्योंकि इस बार यह काम उतना आसान नहीं था। शाह एक कद्दावर नेता होने के साथ राजनीतिक गणित को समझने में माहिर है। अमित शाह जमीनी हकीकत से हमेशा वाकिफ रहते हैं। उनके पास तमिलनाडु को लेकर साफ तस्वीरें हैं, सुस्पष्ट एजेंडा है। वह एआईडीएमके के साथ अभी से उदार एवं लचीली सोच से चलना चाहते हैं लेकिन उन्हें अपना लक्ष्य पता है। डीएमके एवं स्टालिन का अहंकार ही उनका मुख्य हथियार होगा। विकास के लिये सत्ता परिवर्तन जनता के लिए भी जरूरी है इसे साबित करने का तरीका भला अमित शाह से ज्यादा कौन जानता होगा। तमिल में भाजपा के पांव जमते हुए दिख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है भाजपा की सोच में बदलाव आना, तमिलों की बारीकियों एवं भावनाओं को समझते हुए राजनीतिक दांव चलना। भाजपा के पास द्रविड़ समाज को आकार देने का भले ही संस्थागत इतिहास नहीं है, लेकिन राज्य के विकास में उसने गहरे संसाधन लगाये हैं। वह एक नया वोट-आधार तैयार कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने काशी और तमिलनाडु के बीच विभेद को खत्म करने की कोशिश की है। धार्मिक राजत्व का तमिल प्रतीक सेंगोल संसद में स्थापित किया गया। ऐसे अनेक सकारात्मक प्रयास भाजपा के द्वारा लगातार किये जा रहे हैं। त्रिभाषा फामूर्ला भी तमिल लोगों को भाषा के नाम पर जोड़े रखने का एक उपक्रम है। मोदी और शाह दोनों ने तमिल भाषा को तमिल के सम्मान को परिभाषित किया। पिछले दशक का एक बड़ा राष्ट्रीय घटनाक्रम यह रहा है कि भाजपा ने चुपचाप अपने नारे हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान में सुधार किया है। अब वे द्रविड़ और सभी क्षेत्रीय भाषाओं की बात करते हैं। इन सबके चलते यदि तमिल के जातीय-मतदाता भाजपा को उसके मौजूदा स्वरूप में स्वीकार करेंगे, तब यह भारतीय सेकुलर राजनीति की एक क्रांतिकारी घटना होगी।

शाह की रणनीति सही दिशा में काम कर रही है। बावजूद यह डगर चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि डीएमके दुबारा सत्ता में आने के लिए जो नुस्खा तैयार कर रही है उसमें तमिल स्वाभिमान और भाषा विवाद का घोल मिलाया जा रहा है। स्टालिन और उनका पूरा परिवार इस समय घोर भ्रष्टाचार और गैर कानूनी कामों में लिप्त है लेकिन उन्होंने हिंदी विरोध, दक्षिण के साथ केन्द्र का कथित सौतेला व्यवहार और मनमाने परिसीमन जैसे मुद्दों को आगामी चुनाव का एजेंडा बनाया है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु यात्रा में जानबूझ कर मुख्यमंत्री स्टालिन गायब रहे, जबकि यह एक सामान्य शिष्टाचार होता है कि प्रधानमंत्री प्रांत में आये तो मुख्यमंत्री उनका स्वागत करें। लेकिन ऐसा न करके स्टालिन ने यह जताया कि डीएमके भाजपा विरोध के साथ-साथ केंद्र से टकराव की राजनीति पर है।

क्या तमिलनाडु में भाजपा व अन्नाद्रमुक पार्टी का साथ जीत ग्यारंटी बनेगा?

अशोक भाटिया

4 अप्रैल को तमिल नववर्ष से पहले, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व सहयोगी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ राज्य में गठबंधन बनाने की घोषणा की। हालाँकि एआईएडीएमके ने एक समय तमिलनाडु के द्रविड़-प्रभुत्व वाले राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, लेकिन अब इसका वही प्रभाव नहीं है जो पूर्व मुख्यमंत्री जे। जयललिता के समय था।पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पाडी के। पलानीस्वामी (ईपीएस) की अगुआई वाली पार्टी अपने पार्टी सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री ओ। पनीरसेल्वम (ओपीएस) के साथ नियंत्रण के लिए तीखे संघर्ष के बाद सत्ता में बनी हुई है। 2016 से 2021 तक भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से जुड़े रहने के कारण, ईपीएस ने भाजपा नेतृत्व के साथ कामकाजी संबंध का आनंद लिया। पिछले हफ़्ते चेन्नई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई घोषणा में भी स्पष्ट राजनीतिक संदेश था कि ईपीएस मौजूदा एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके गठबंधन सरकार के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र अभी समाप्त हुआ है और सत्र के अंत में, लोकसभा और राज्यसभा में मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक पर एक हंगामेदार बहस हुई। विधेयक का विरोध करने के लिए भाजपा का विपक्ष एक साथ आया था। कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस,डीएमके सहित विपक्षी दल। एआईएडीएमके ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त की थीं। इतना ही नहीं एआईएडीएमके के सांसदों ने राज्यसभा में भी वक्फ सुधार सरकार के खिलाफ वोट किया था। तो अब सवाल यह उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी और एआईएडीएमके दोनों ही बहुत करीब आ गए? अमित शाह एक राजनयिक राजनेता हैं और राजनीतिक कूटनीति में चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं। एक राजनीतिक दल जो संसद में भाजपा का समर्थन नहीं करता है, वह राजनीतिक दल जिसने पिछले चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया था, एआईएडीएमके, वह पार्टी जिसने एनडीए में फिर से प्रवेश किया। ये सारी घटनाएं इतनी तेजी से घटीं कि इसने देश के सभी राजनीतिक दलों को हैरान कर दिया। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए एआईएडीएमके पार्टी के साथ जल्दबाजी में गठबंधन क्यों किया गया, इसका रहस्य कई लोगों के सामने नहीं आया है।

इससे पहले, भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत बढ़ाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा दी थी, और अब भाजपा अन्नाद्रमुक को फिर से गठबंधन करके चेन्नई के सिंहासन से एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार को गिराने की पूरी कोशिश कर रही है। भाजपा पिछले 10-12 वर्षों से तमिलनाडु में पार्टी का विस्तार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने महसूस किया है कि द्रमुक बनाम अन्नाद्रमुक की लड़ाई में भाजपा का कोई लाभ नहीं है। भाजपा और एआईएडीएमके दोनों ने महसूस किया है कि अगर वे डीएमके को सत्ता से हटाना चाहते हैं तो उन्हें एक साथ आने की जरूरत है। यही कारण है कि अमित शाह ने खुद चेन्नई में घोषणा की कि भाजपा-अन्नाद्रमुक गठबंधन राजनीतिक उदासीनता से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।

भाजपा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अन्ना मलाई अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन बनाने में एक बड़ी बाधा थे। अन्ना मलाई खुद एक जुझारू नेता हैं। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने डीएमके सरकार के खिलाफ लड़ते हुए पार्टी में जान डाल दी और पार्टी की नींव मजबूत की। जहां भाजपा से कोई नहीं पूछता, भाजपा से कोई नहीं पूछ रहा है, भाजपा का कोई कैडर नहीं।अन्ना मलाई ने ऐसे राज्यों में भाजपा के वोट शेयर को तीन से 11 प्रतिशत तक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लिए अन्ना मलाई के प्रदर्शन को नजरअंदाज करना और उन्हें पद से हटाना मुश्किल था। अन्ना मलाई एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। वे युवा हैं। 2019 में, उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने अपने दमदार काम से मोदी-शाह का दिल भी जीत लिया। उनके काम को देखते हुए उन्हें तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने सत्ताधारी डीएमके सरकार के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया। वे स्टालिन सरकार को परेशान करते रहे। स्पष्ट है कि सबको लग रहा था बीजेपी तमिलनाडु में 2026 का विधानसभा चुनाव अन्ना मलाई के नेतृत्व में लड़ेगी। यह भी चर्चा थी कि अन्ना मलाई आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। सभी ने महसूस किया कि राजनीति में ऐसा नहीं होता जैसा दिखता है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने रोटी पलट दी। अचानक अन्ना मलाई को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया था। शीर्ष नेतृत्व को यकीन था कि द्रमुक के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा जब तक कि उन्हें राज्य अध्यक्ष के पद से हटा नहीं दिया जाता। इसलिए पार्टी ने उनके स्थान पर नयनार नागेंद्र को नियुक्त किया और तुरंत भाजपा-द्रमुक गठबंधन के गठन की घोषणा की। 64 वर्षीय नयनार नागेंद्रन ने 12 अप्रैल को भाजपा के तमिलनाडु राज्य अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। नागेंद्रन एक मृदुभाषी व्यक्तित्व हैं। वे दक्षिण तिरुनेलवेली निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। वह अन्ना मलाई की तरह आक्रामक नहीं हैं। तो पार्टी के एजेंडे को कैसे लागू किया जाएगा? गठबंधन भाजपा एआईएडीएमके नेताओं की बातों को स्वीकार कर गठबंधन चलाना चाहती है। स्टालिन सरकार को हराना ही भाजपा-एआईएडीएमके गठबंधन के सामने एकमात्र एजेंडा है।

लोकसभा चुनाव के मामले में तमिलनाडु पांचवां सबसे बड़ा राज्य है। भाजपा ने कर्नाटक में पैठ बनाई, लेकिन केरल और तमिलनाडु में ज्यादा पैठ नहीं बना सकी, और अब, 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले, भाजपा ने पार्टी विस्तार का एजेंडा तैयार करने के लिए अन्नाद्रमुक को फिर से गठबंधन किया है।भाजपा ने तमिलनाडु में 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ा था। इस चुनाव में भाजपा को 11 फीसदी वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में भाजपा का कोई भी उम्मीदवार सांसद नहीं चुना गया था। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अन्ना मलाई भी हार गए थे। भाजपा आलाकमान ने महसूस किया कि पार्टी का तमिलनाडु में कोई बड़ा आधार नहीं है और अपने दम पर चुनाव लड़ना लाभदायक नहीं है।

जैसे ही एक पुराने सहयोगी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का विचार पार्टी में जोर पकड़ने लगा, एआईएडीएमके पार्टी, जिसने भाजपा छोड़ दी थी, को फिर से भाजपा द्वारा दरकिनार कर दिया गया। संसद सत्र के अंत में, एआईएडीएमके नेता दिल्ली गए और अमित शाह के साथ बातचीत की और अमितभाई भाजपा-अन्नाद्रमुक गठबंधन की घोषणा करने के लिए चेन्नई गए।2024 के लोकसभा चुनावों में, उद्ध सांसदों ने तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर जीत हासिल की। उद्ध को 46।9 प्रतिशत वोट मिले। यह 1991 के बाद से उद्ध द्वारा सबसे अधिक वोट शेयर था। 2024 में, भाजपा ने तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से 23 पर चुनाव लड़ा, लेकिन हर जगह हार गई। भाजपा को 2019 के लोकसभा चुनावों में 3.6 प्रतिशत, 2024 में 5.5 प्रतिशत वोट मिले। 2009 में, इसे 2।3 प्रतिशत वोट और 2004 में 5.1 प्रतिशत वोट मिले। द्रमुक के पास अन्नाद्रमुक और भाजपा की तुलना में बड़ा समर्थन आधार है। स्टालिन के पास पलानीस्वामी की तुलना में बड़ा समर्थन आधार है, लेकिन उन्हें सत्ता विरोधी लहर से भी पीड़ित होने की संभावना है। तमिलनाडु में, भाजपा ने अन्नाद्रमुक को महत्व दिया है। डेढ़ साल के अंतराल के बाद, भाजपा और अन्नाद्रमुक ने गठबंधन में फिर से प्रवेश किया है।

हाल ही में आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) नेतृत्व का मानना रहा है कि तमिलनाडु में डीएमके का मुकाबला करने के लिए भाजपा के पास मजबूत कैडर बेस की कमी है। भाजपा का मानना है कि एआईएडीएमके के साथ गठबंधन अगले साल विधानसभा चुनावों से पहले स्टालिन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था को प्रमुख मुद्दे बनाने में एक ताकत के रूप में काम करेगा।संघ के लिए द्रविड़ मतदाता अब द्रविड़ पार्टियों के पक्ष में चुनावी यथास्थिति में विश्वास नहीं करता। भाजपा के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, ₹अब आजीविका, काम के अवसर और भ्रष्टाचार बड़े मुद्दे हैं, और हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ भावनाओं का भड़कना भी बड़ा मुद्दा है।

ज्ञात हो कि किसी समय तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता, जिन्हें अम्मा के नाम से जाना जाता है, एआईएडीएमके की शक्तिशाली नेता थीं। मुख्यमंत्री बनने से पहले, वह तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष की नेता थीं। 25 मार्च, 1989 की घटना ने विधानसभा में भारी हंगामा किया था। हंगामा मच गया। उस दिन राज्य का बजट पेश किया जाना था। हालांकि, जैसे ही विपक्ष की नेता जयललिता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ अवैध कार्रवाई की है, न केवल उनके फोन टैप किए जा रहे थे, द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच खींचतान शुरू हो गई। किसी ने जयललिता की साड़ी खींची, किसी ने उसके बाल खींचे। एक ऐसी घटना जिसने संसदीय लोकतंत्र को काला कर दिया। जयललिता ने संकोच नहीं किया। उसने दृढ़ता से कहा झ आज मेरे साथ जो हुआ उसका जवाब मैं जरूर दूंगी। अगली बार जब मैं सदन में कदम रखूंगी, मुख्यमंत्री के रूप में.... जयललिता दो साल बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सदन में दोबारा पहुंची हैं। उसने अपनी बात सच कर दी। 1991 से 2016 तक, वह 14 साल से अधिक यानी 5238 दिनों तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं।

दंगों की स्क्रिप्टः जब वक्फ बन जाए हिंसा का बहाना

-सुरेश गांधी

वक्फ बोर्ड संशोधन पर पूरे देश में बहस छिड़ गई है. एक तरफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की बात हो रही है, तो दूसरी ओर हिंसा का विरोध किया जा रहा है. लेकिन मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा से पता चलता है कि वक्फ बोर्ड के विरोध की आड़ में किसी बड़ी साजिश का षडयंत्र रचा जा रहा है। इस षडयंत्र में विपक्ष के साथ-साथ सीमा पर कुछ आतंकी संगठने भी अपना रंग दिखा रही है। वैसे भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने बांग्लादेश से मोर्चा खोल रखा है. अब तो वक्फ बिल के विरोध के लिए एक पार्टी को भी हुकम जारी किया जा चुका है. खबर है कि बांग्लादेश खिलाफत मजलिस ने वक्फ के विरोध में भारतीय उच्चायोग के घेराव के लिए बाकायदा 23 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है. इसी पार्टी ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ जमात के साथ मिलकर ढाका की सकड़ों पर गदर मचाया था. मुसीर्दाबाद सहित बंगाल में जगह-जगह फैली हिंसा को इन्हीं साजिशों से जोड़कर देखा जा रहा है। आरोप है कि बंगाल में ममता सरकार इस साजिश का हिस्सा है। अलग बात है कि वक्फ बिल पर मुसलमानों में ही छिड़ गई तगड़ी ह्लजंगह्ल! मतलब साफ है वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में भड़काई गई सुनियोजित हिंसा से यदि सरकार या या यूं कहे प्रशासन समय रहते ही नहीं चेता तो आने वाले दिनों में अंजाम और भी बुरे होने से इनकार नहीं किया जा सकता

वक्फ बिल अब कानून का रूप ले चुका है. संसद में देश के सामने यह कानून बना. कानून से किसी को आपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. कई याचिकाएं गई भी हैं. सुप्रीम कोर्ट इसकी वैधता पर सुनवाई करेगा और अपना फैसला लेगा. ऐसे में किसी को भी हक नहीं कि वक्फ कानून की आड़ में देश के माहौल को खराब करे. मगर पश्चिम बंगाल में माहौल बिगड़ चुका है. खास यह है कि मुर्शिदाबाद के एक इलाके से फैली हिंसा की आग अब धीरे-धीरे फैलती जा रही है. पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन जारी हैं. वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमान सड़कों पर हैं. उन्हें बरगलाया जा रहा है. इसकी वजह से सैकड़ों हिंदुओं का पलायन हो चुका है. तीन लोगों की जान भी जा चुकी है. अब सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल में ही सबसे अधिक मुसलमान हैं? क्या अन्य राज्यों के मुसलमानों को वक्फ कानून से कोई लेना-देना नहीं? आखिर यूपी-बिहार और महाराष्ट्र के मुसलमान क्यों बेफिक्र हैं? पश्चिम बंगाल में आखिर कौन दंगे की बार-बार साजिश रच रहा है? जबकि सरकार का दावा है कि इससे गरीब मुस्लिमों को फायदा होगा. अगर कुछ लोगों को वक्फ एक्ट पर गुस्सा है तो गरीबों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? बावजूद इसके विपक्ष और मुस्लिम संगठन पुराने वक्फ बोर्ड के नियमों को लेकर अड़े हुए हैं.

वक्फ कानून को लेकर बंगाल की सियासत ने इस हिंसा को और हवा दी है. इसकी वजह से ही बंगाल में अब मार-काट मच चुका है. आरोप है कि टीएमसी वाले ही इस कानून के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं. मुर्शिदाबाद में हिंसा, आगजनी और पत्थरबाजी ने यह साबित कर दिया है कि बगैर सियासी घी के यह हिंसा नहीं हो सकती थी. मुर्शिदाबाद हिंसा का टूलकिट भी सामने आया है, जिसमें टेलीग्राम, व्हाट्सऐप और सिग्नल ऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से टूलकिट जारी किया जा रहा है. कहां-कैसे प्रदर्शन करना है, सब प्लानिंग हो रही है. खुफिया एजेंसियों की मानें तो बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में फैली हिंसा का पैटर्न साल 2019 में सीए के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों की तरह है. मुर्शिदाबाद में हिंसा फैलाने के लिए उसी टूलकिट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका प्रयोग सीएए के खिलाफ हुए विरोध-प्रदर्शनों में किया गया था. आरोप यह भी है ममता सरकार के लोग ही दंगा करने वालों को उकसा रहे है। वह नहीं चाहती कि जिन लोगों ने वक्त की आड़ में जमीनों को कब्जा किया है, वह उजागर हो। इसीलिए साजिश के तहत दंगा करवाया जा रहा है। ये वहीं लोग है, जो कभी दलित-मुस्लिम समीकरण तैयार करवाते हैं तो कभी मुस्लिम-ओबीसी समीकरण को फंडिंग करवाते हैं। इसी की आड़ में अभिजात्य मुसलमान विदेशों से हवाला के जरिए फंडिंग लेकर देश में पाकिस्तान-बांग्लादेश के ही नहीं बल्कि अरब देशों के हमदर्द पैदा करते हैं।

जबकि हकीकत तो यह है कि नये वक्फ कानून से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, वक्फ की लाखों हेक्टेयर जमीन और बेशकीमती प्रॉपर्टी से मुस्लिम महिलाओं, बेवाओं, नौजवानों और पसमंदा मुसलमानों का भला होगा। मतलब साफ है अब वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी, वक्फ बोर्ड कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं की जागीर नहीं बनेगा। कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति से मुसलमानों की हुए नुकसान की भरपाई होगी। वक्फ की आड़ में कब्जा करने वाले लैंड माफियाओं का बैंड बजेगा। कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों के झांसे में आकर पंचर बनाते रहने वाले गरीब मुसमानों का भला होगा। लेकिन यह सब तभी संभव हो पायेगा जब तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों को उन दलों को सबक सिखाना होगा, जो उन्हेकं वोट बैंक के रुप में उनका इस्तेमाल करते है। उन्हें समझना होगा आखिर क्या वजह है वो अपनी मेहनत के दम पर डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, वैज्ञानिक क्यों नहीं सके। उन्हें देखना होगा कि आखिर वजहों से गरीब पिछड़े मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। मजहब को तरजीह देकर उन्हें क्यों पढ़ाई लिखाई में पीछे रखा गया। उन्हें जानना होगा कि जब राशन, मकान, बिजली, इलाज जैसी सुविधाओं में भेदभाव नहीं हो रहा है कैसे मोदी सरकार मुसलमान विरोधी हो सकती है। बंगाल के मुसलमान जिस दिन समझ जायेगा ममता के लिए वो 30 प्रतिशत मुस्लिम एक बड़ा वोट बैंक के सिवाय कुछ नहीं है, उसी दिन से उनका भला होने लगेगा।

दरअसल, नए वक्फ संशोधन कानून अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने पर रोक लगाती है. आदिवासी संगठन इसे अपने समुदाय के हितों की रक्षा के लिए एक जरूरी प्रावधान मान रहे हैं. उनका कहना है कि संविधान निमार्ताओं ने आदिवासियों की जमीनों को लेकर विशेष रूप से चिंतित रहे. इसका परिणाम है तमाम राज्यों के ऐसे कानून जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की जमीनों का ट्रांसफर गैर-आदिवासी को करने पर प्रतिबंध लगाते हैं. वक्फ कानून, 1995 में वक्फ बोर्ड को अनियंत्रित शक्ति दे दी गई थी. ऐसे तमाम उदाहरण हैं, जहां वक्फ बोर्ड ने आदिवासियों की जमीन को वक्फ बताकर उस पर कब्जा कर लिया. संसद से बना नया वक्फ संशोधन कानून आदिवासी समाज के हितों के प्रति केंद्र सरकार की वचनबद्धता को दिखाता है. लंबे समय से ऐसे कानून की जरूरत महसूस की जा रही थी. तो दुसरी तरफ नए वक्फ कानून के विरोध में कांग्रेस, आरजेडी, सपा, टीएमसी, डीएमके, लेफ्ट जैसे राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी समेत कई संगठनों और लोगों ने याचिकाएं दाखिल की हैं. उन्होंने नए कानून को मुस्लिमों से भेदभाव करने वाला बताया है. इस तरह की 20 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई हैं.

बता दें, वक्फ एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ है ह्लरोक देनाह्व या ह्लसमर्पित कर देनाह्व। इस्लाम में वक्फ का मतलब किसी संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से दान देना, ताकि उसका लाभ आम गरीब जनता या धार्मिक संस्थाओं को मिलता रहे। खास यह है कि एक बार संपत्ति वक्फ हो गई तो उसे न बेचा जा सकता है, न विरासत में दिया जा सकता है। वक्फ का उद्देश्य किसी धार्मिक, शैक्षिक, या सामाजिक कार्य को समर्थन देना होता है। वक्फ संपत्ति की देखरेख और प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति को मुतवल्ली नियुक्त किया जाता है। वक्फ एक कानूनी संस्था होती है जिसे किसी कोर्ट या कानून के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होती है। भारत में वक्फ की शुरूआत मुगल काल (1526 से 1857) से है। मुगलों के शासनकाल में कई अमीर, नवाबों और राजाओं ने मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों व सरायों आदि के निर्माण हेतु जमीनें वक्फ की थीं। ये संपत्तियां आमतौर पर धार्मिक या परोपकारी गतिविधियों के लिए होती थीं। ब्रिटिश काल (1858 से 1947) तक वक्फ संपत्तियों को लेकर कई कानूनी विवाद उत्पन्न हुए। इन्हें स्पष्ट करने के लिए 1913 में एक्ट बनाया गया, जिससे वक्फ को कानूनी मान्यता मिली। राज्य वक्फ बोर्डों की स्थापना इसी के तहत की गई। 1995 इस कानून ने वक्फ बोर्डों को कांग्रेस द्वारा वोटबैंक खातिर अधिक शक्तियां दे दी गई थीं। 2013 में वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण से बचाने के लिए कड़े नियम बनाए गए। वक्फ संपत्ति के विवाद निपटाने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल बनाए गए। आंकड़ो के मुताबिक कुल 5 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां है, जिसका दायरा कुल क्षेत्रफल 6 लाख एकड़ से अधिक है। खास यह है कि सबसे अधिक वक्फ संपत्ति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है।

सरकारी दावों की मानें तो रेल और रक्षा के बाद वक्फ के पास देश में सर्वाधिक संपत्ति है। आरोप है कि इसमें अधिकांश जमीने जबरन हड़पी गयी है। उसी कड़ी में इस एक्ट में परिवर्तन किया गया है। हालांकि धार्मिक संस्थाओं में समय-समय पर व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है। देखा जाएं तो बहुत सारी धार्मिक संस्थाओं में कोर्ट के हस्तक्षेप से काफी सुधार हुए हैं और होते रहते हैं। सबरीमाला से लेकर अन्य तमाम व्यवस्थाओं में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। निश्चित रूप से इन परिवर्तनों को राजनीतिज्ञ अपने चश्मे से देखते हैं और समाज में उससे संबंधित लोगों का अपना नजरिया है। परंतु राजनीतिक चुनौतियों के बीच हमें देश के आम नागरिक के रूप में इसे लेना चाहिए। निश्चित रूप से राजनीतिक दलों, न्यायालयों और एक जिम्मेदार नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह इस संशोधन बिल को किसी समुदाय या राजनीतिक दल की हार-जीत के साथ जोड़कर न देखें। वक्फ की इतनी बड़ी संपत्ति विशेष करके, जिसमें उनके मालिक, जिन्हें मुतवल्ली कहा जाता है, उनके द्वारा समय-समय पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले सामने आते रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी दुर्दशा उन तलाकशुदा, विधवा महिलाओं की रही, जिन्हें वसीयत के आधार पर वंचित करके रखा गया, जबकि वही वास्तव में उसकी उत्तराधिकारी होतीं। लेकिन महिलाओं को अधिकार न देने के कारण निश्चित रूप से जो लैंगिक आधार पर समता-समानता की बात है, वह पुराने वक्फ कानून में नहीं थी।

इस नए बिल में उसमें भी सुधार लाया गया है। वक्फ का उद्देश्य था कि वह अपने समुदाय के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा जैसे संसाधनों की पूर्ति करेगा, लेकिन वक्फ के मुतवल्ली के जो अधिकार थे उससे वह पूर्ति नहीं हो पा रही थी। बहुत सारी संपत्तियां, जो दशकों से सौ-पचास रुपए किराए पर थी, जिनका किराया आज कई हजारों में हो सकता है और जिससे बहुत बड़ा राजस्व आ सकता है, वह सब लोकहित में न रहकर मुतवल्ली और उससे संबंधित व्यक्तियों के हित में ही रह गई थी। इसमें सुधार व परिवर्तन इस नए बिल में हुआ है। नई नीतियों से वक्फ सम्पत्तियों की अवैध बिक्री व बबार्दी रुकेगी, जो वक्फ के अयोग्य संरक्षकों द्वारा पहले की जाती रही है क्योंकि अब उनका एकाधिकार नही रहेगा। इससे जो सम्पत्ति अर्जित होगी वह पूर्णतः मुस्लिमों के कल्याण के लिए होगी। जो नए बिल के आने से काफी बड़ी धनराशि भी हो सकती है। इन सभी बातों को इस नए बिल में लाने की कोशिश की गई है। साथ ही जवाबदेही जो किसी भी संस्था को चलाने के लिए आवश्यक है उसकी सामूहिक जिम्मेदारी जिससे एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था विकसित होती है और पारदर्शिता बनी रहती है, वह सब इस वक्फ संशोधन बिल में पूरी तरह से शामिल है। इस संशोधन बिल पर जिस प्रकार से पक्ष और विपक्ष द्वारा इसे किसी समुदाय से जोड़ करके बयान दिए जा रहे हैं, उससे लगता है कि राजनीति भी अब लोकहित के लिए नहीं है बल्कि राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता में ही सीमित होती जा रही है, जो किसी भी सशक्त और समर्थ लोकतंत्र के लिए कदापि उचित नहीं है। यहां यह समझना होगा कि वक्फ संशोधन किसी पार्टी का नहीं है बल्कि यह संशोधित बिल देश हित में लाया गया एक प्रयास है और जिसमें पारदर्शिता और समावेशन को सुनिश्चित किया गया है। इसमें जिस प्रकार माफिया लोगों का आतंक था और दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति थी, उस पर इसमें अंकुश लगाने की पूरी कोशिश की गई है।

यहां सरकार की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि इसका कदापि गैर इस्लामिक प्रयोग नहीं होगा। नए वक्फ बिल में कुछ ऐसी चीज हैं जिनका आज के दौर में होना बहुत आवश्यक है जैसे टेक्नोलॉजी को जोड ?ा, ट्रिब्यूनल को अधिकार देना, ट्रिब्यूनल से संतुष्टि न होने पर शीर्ष कोर्ट जाने का विकल्प, तलाकशुदा महिलाओं-विधवाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना प्रमुख है। जहां तक मुशीर्दाबाद के दंगे का सवाल है तो वहां मुस्लिमों की आबादी अधिक है. कुल आबादी के सापेक्ष 66.3 फीसदी मुस्लिम हैं. जबकि यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में भी मुस्लिम 18 से 22 फीसदी हैं. फिर यहां के मुसलमान इतने बेफिक्र क्यों हैं? क्या इन राज्यों में मुसलमान नहीं रहते? दरअसल, सारा खेल सियासी है. 2011 की जनगणना की मानें तो भारत में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले पांच राज्य हैं- यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और असम. उत्तर प्रदेश में 3.84 करोड़ मुस्लिम यानी 19.26 फीसदी, पश्चिम बंगाल में 2.46 करोड़ मुस्लिम यानी 27.01 फीसदी, बिहार में 1.75 करोड़ मुस्लिम यानी 16.87 फीसदी महाराष्ट्र में 1.29 करोड़ मुस्लिम यानी 11.54 फीसदी, असम में 1.06 करोड़ मुस्लिम यानी 34.22 फीसदी मुस्लिम है। और इन्हीं मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने की कवायद सियासी दलों द्वारा चला जा रहा है।

घरों की बिक्री और नए लॉन्च में पहली तिमाही में गिरावट

मुंबई। जनवरी-मार्च तिमाही में भारत के आठ प्रमुख आवासीय बाजारों में घरों की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में 19% घट गई, क्योंकि संपत्ति की बढ़ती कीमतों और धीमी होती आर्थिक वृद्धि ने खरीदारों को सतर्कता बरतने को मजबूर कर दिया। यह जानकारी डिजिटल रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन और एडवाइजरी प्लेटफॉर्म प्रॉपटाइगर डॉटकॉम की नवीनतम रिपोर्ट में दी गई है। प्रॉपटाइगर डॉटकॉम मूल रूप से आरईए इंडिया का हिस्सा है, जिसके पास हाऊसिंग डॉटकॉम का मालिकाना हक भी है। इसकी ओर से जारी रियल इनसाइट रेजिडेंशियलः द1 2025 रिपोर्ट (जनवरी-मार्च 2025) के अनुसार नए घरों की आपूर्ति में भी इस कैलेंडर वर्ष की पहली तिमाही में 10% की गिरावट दर्ज की गई। पिछले कुछ वर्षों में संपत्ति की कीमतों में नाटकीय बढ़ोतरी के चलते डेवलपर्स ने अपनी उम्मीदों में बदलाव किया, जिससे दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश के एक बड़े वर्ग के लिए घर खरीदना अब और भी कठिन हो गया है। हाऊसिंग डॉटकॉम और प्रॉपटाइगर डॉटकॉम के ग्रुप सीईओ श्री ध्रुव अग्रवाल ने कहा, ह्लकीमतों में तेज बढ़ोतरी ने पहले ही बिक्री पर प्रतिकूल असर डालना शुरू कर दिया था। अब ग्लोबल टैरिफ वॉर जैसी नई अनिश्चितताओं के बीच यह स्वाभाविक है कि खरीदार रियल एस्टेट जैसे बड़े निवेश में सतर्कता बरतें। यदि भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की दर कटौती की घोषणा नहीं की होती, तो यह गिरावट और भी अधिक हो सकती थी। रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी-मार्च तिमाही में एक लाख से कम आवासीय इकाइयाँ ही बेची गईं। रिपोर्ट में शामिल अधिकांश शहरों में बिक्री में गिरावट देखी गई। हालांकि बेंगलुरु और चेन्नई इस ट्रेंड से बाहर रहे। हैदराबाद, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (एमएमआर) और पुणे में बिक्री में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। बेंगलुरु में 2024 के पहली तिमाही के तुलना में 11,731 की इकाइयों की बिक्री के साथ 13% की वृद्धि दिखाई दी। चेन्नई में 4,774 इकाइयों की बिक्री के साथ 8% की वृद्धि दिखाई दी। वहीँ अन्य प्रमुख शहरों में बिक्री में गिरावट दिखाई दी। जहाँ अहमदाबाद में 10,730 (-17%), दिल्ली एनसीआर में 8,477 (-16%), हैदराबाद 10,647 (-26%), कोलकाता 3,803 (-1%), मुंबई 30,705 (-26%) और पुणे में 17,228 (-25%) इकाइयों की बिक्री हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि बाजार में मूल्य-सुधार (मार्केट करेक्शन) के संकेत भी नई आपूर्ति में गिरावट के रूप में सामने आए। आठ में से पांच शहरों में लॉन्च में साल-दर-साल गिरावट दर्ज की गई। पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद में नई परियोजनाओं की शुरूआत में सबसे तेज गिरावट देखी गई। पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद में 2024 के पहली तिमाही के तुलना में नए लॉन्च की इकाइयों में क्रमशः 15,543 (-38%), 10,156 (-33%) और 2,384 (-23) की भारी गिरावट दिखाई दी। अन्य प्रमुख शहरों जैसे चेन्नई 4,070 (-14%), मुंबई 31,322 (-15%) भी गिरावट देखी गई। वहीं बेंगलुरु 18,183 (82%), दिल्ली एनसीआर 7,952 (16%) और कोलकाता 3,354 (138%) में नए लॉन्च इकाइयों में वृद्धि हुई।

कैटरपिलर इंक. का 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का संकल्प

मुंबई। विश्व की अग्रणी निर्माण एवं खनन उपकरण, ऑफ-हाइवे डीजल और प्राकृतिक गैस इंजनों, औद्योगिक गैस टरबाइनों तथा डीजल-इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की निमार्ता कंपनी कैटरपिलर इंक. अपनी ऐतिहासिक 100वीं वर्षगांठ मना रही है। इस अवसर पर, कैटरपिलर इंक. ने वैश्विक स्तर पर अगले पाँच वर्षों में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का संकल्प लिया है, ताकि भविष्य के कार्यबल को आवश्यक कौशल प्रदान किया जा सके। कैटरपिलर के इंडिया कंट्री मैनेजर एवं वाइस प्रेसीडेंट इंटीग्रेटेड कंपोनेंट सॉल्यूशंस इंजीनियरिंग डिवीजन भुवन आनंदकृष्णन ने कहा, ₹कैटरपिलर में नवाचार और ग्राहक-केंद्रितता हमारी सफलता की मूल आधारशिलाएं रही हैं। जब हम वैश्विक स्तर पर 100 वर्ष तथा भारत में 50 से अधिक वर्षों का सफर पूरा कर रहे हैं, हमारी उपलब्धियों के पीछे हमारे कर्मठ कर्मचारी ही प्रमुख शक्ति हैं। उनका समर्पण न केवल भारत की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर नए मानक भी स्थापित किए हैं। हम एक अधिक सतत, कुशल एवं तकनीकी रूप से उन्नत भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं और मिलकर हम अगले शताब्दी की प्रगति को आकार देंगे। इस अवसर पर कैटरपिलर इंडिया टीम को इस गौरवपूर्ण विरासत में अपनी भूमिका पर अत्यधिक गर्व है। भारत में बीते 50 वर्षों से अधिक समय से संचालन करते हुए, कैटरपिलर ने देश की अधोसंरचना के निर्माण एवं औद्योगिक प्रगति में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के वैश्विक निर्माण केंद्र के रूप में उभरते महत्व को देखते हुए, कैटरपिलर देश की औद्योगिक एवं अधोसंरचना संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति में निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और कुशल मानव संसाधन के साथ, कैटरपिल एमर भारत की विकास यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। यह पहल दुनिया भर में हो रहे डिजिटल परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, तकनीक के माध्यम से वैश्विक बाजार की बदलती मांगों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विशेषज्ञों की मुहर: बादाम से सुधरता है दिल और मेटाबॉलिज्म का स्वास्थ्य, वजन कम करने में भी मददगार

मुंबई/पटना। एक नए प्रकाशन में, दुनिया के बड़े स्वास्थ्य और पोषण विशेषज्ञों ने बताया है कि रोजाना बादाम खाने से दिल और शरीर की चयापचय (मेटाबॉलिज्म) सेहत अच्छी रहती है। 11 वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने बादाम और कार्डियोमेटाबॉलिक स्वास्थ्य पर अब तक हुई रिसर्च का विश्लेषण किया और इस बात पर सहमति जताई कि बादाम का नियमित सेवन कई प्रमुख स्वास्थ्य क्षेत्रों में लाभ पहुंचा सकता है। विशेषज्ञों ने पाया कि रोजाना बादाम खाना एक प्रभावी और प्रमाणित खानपान रणनीति है, जो हृदय स्वास्थ्य, वजन नियंत्रण और पाचन तंत्र (गट माइक्रोबायोम) को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। इस सहमति पत्र में यह भी बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 50 ग्राम (1.8 औंस या लगभग दो मुट्ठी) बादाम का सेवन करता है, तो कुछ मामलों में मामूली रूप से वजन घटाने में भी सहायता मिल सकती है। करंट डेवलपमेंट्स इन न्यूट्रिशन में प्रकाशित सहमति पत्र, आमंड बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया द्वारा वित्त पोषित एक वैज्ञानिक गोलमेज सम्मेलन के बाद तैयार किया गया है। इसमें रोजाना बादाम खाने के फायदे बताए गए : पूरी दुनिया में कार्डियोमेटाबॉलिक बीमारियाँ (दिल और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याएँ) बढ़ रही हैं, इसलिए यह समझना जरूरी है कि बादाम इंसान की सेहत को कैसे बेहतर कर सकते हैं। डॉ. एडम ड्रेवनोव्स्की, जो इस शोध के सह-लेखक हैं और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में महामारी विज्ञान के प्रोफेसर और दुनिया के जानेमाने न्यूट्रीशन एक्सपर्ट हैं, ने कहा, बादाम पोषक तत्वों का खजाना हैं और ये दुनिया में सबसे ज्यादा शोध किए गए खाद्य पदार्थों में से एक हैं। दुनिया भर के शोधकताओं ने बादाम और कार्डियोमेटाबॉलिक स्वास्थ्य पर चर्चा की और उन्होंने अपनी-अपनी जानकारियां एवं नजरिये प्रस्तुत किये। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि बादाम कार्डियोमेटाबॉलिक सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं।

अमित शाह को हमें शिवाजी महाराज के बारे में नहीं बताना चाहिएः उद्धव ठाकरे

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने नासिक में एक पार्टी कार्यक्रम में कहा कि मुंबई को लूटा जा रहा है, सब कुछ गुजरात ले जाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि राज्यपाल का निवास कहीं और स्थानांतरित किया जाए, मुंबई स्थित राजभवन को शिवाजी महाराज के स्मारक में तब्दील किया जाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने भाजपा से रास्ता अलग किया है, मरते दम तक हिंदुत्व को नहीं छोड़ूंगा। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना (यूबीटी) के कार्यक्रम में कहा कि मैं भाजपा द्वारा हिंदुत्व के स्वरूप में की जा रही छेड़छाड़ को स्वीकार नहीं करूंगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना के बिना भाजपा अयोध्या में राम मंदिर बनाने की स्थिति में नहीं पहुंच पाती।

उद्धव ठाकरे ने कहा कि चार दिन पहले अमित शाह रायगढ़ आए थे और एक बार उनका जिक्र करते हुए कहा था, शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन जब शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा तो इसकी खबर लंदन गजट में छपी।

इसलिए अमित शाह को हमें शिवाजी के बारे में नहीं बताना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने भाजपा को चुनौती दी कि यदि वे शिवाजी महाराज के बारे में इतना ही सोचते हैं तो वे शिव जयंती पर पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करें। शिवाजी महाराज के प्रति भाजपा के रुख को पाखंडपूर्ण बताते हुए उद्धव ठाकरे ने पूछा कि अरब सागर में शिव स्मारक कब बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी आए और समुद्र में भूमि पूजन समारोह किया। चूंकि उस समय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, इसलिए हमने भी सोचा कि वहां एक स्मारक होगा। शिवाजी महाराज से महान कोई नहीं हो सकता। उदयनराजे ने कहा कि राज्यपाल भवन में शिवाजी महाराज का स्मारक बनाया जाना चाहिए। शिवाजी महाराज के लिए एक भव्य स्मारक बनाएं।

मरते दम तक हिंदुत्व को नहीं छोड़ूंगा

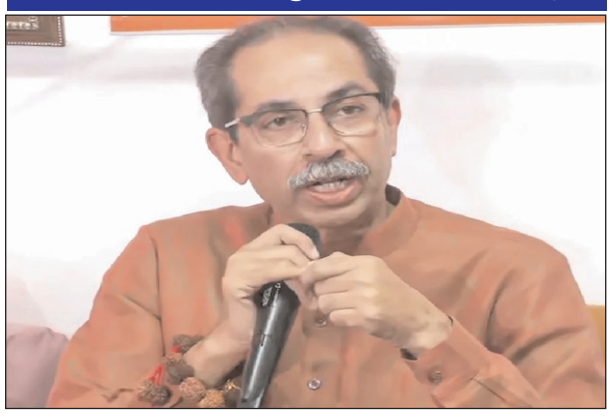

एसबीआई कार्ड और टाटा डिजिटल की टाटा न्यू एसबीआई कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी

मुंबई। एसबीआई कार्ड, भारत के सबसे बड़े प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता, ने आज टाटा डिजिटल के साथ साझेदारी में टाटा न्यू एसबीआई कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की। अपनी तरह का यह अनूठा लाइफस्टाइल को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विभिन्न क्षेत्रों के जागरुक ग्राहकों के लिए एक प्रीमियम और अत्यधिक फायदेमंद वाली खरीदारी का अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस को-ब्रांडेड कार्ड को दो वेरिएंट टाटा न्यू इनफिनिटी एसबीआई कार्ड और टाटा न्यू प्लस एसबीआई कार्ड में लॉन्च किया गया है। ग्राहक सभी खर्चों पर रिवार्ड अर्जित करते हैं, चाहे ऑनलाइन हों या इन-स्टोर, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मर्चेंट आउटलेट्स पर न्यूकॉइन्स के रूप में, जिन्हें टाटा न्यू ऐप पर रिडीम किया जा सकता है। इस लॉन्च के साथ, टाटा न्यू एसबीआई कार्ड के ग्राहक अब एक बेहतर खरीदारी अनुभव के लिए कई तरह के लाभों का आनंद ले सकते हैं। कार्डधारक टाटा न्यू इनफिनिटी एसबीआई कार्ड के साथ खर्च पर 10% तक और टाटा न्यू प्लस एसबीआई कार्ड के साथ खर्च पर 7% तक न्यूकॉइन्स के रूप में पुरस्कार का आनंद ले सकते हैं। ये मासिक रूप से कार्डधारक के टाटा न्यू ऐप के भीतर न्यूपास खाते में जमा किए जाते हैं। इन न्यूकॉइन्स को किराने का सामान, यात्रा बुकिंग, आभूषण, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और फामेर्सी सेवाओं सहित उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में ऑनलाइन और इन-स्टोर दोनों जगह भुनाया जा सकता है, जो ग्राहकों की विभिन्न जीवनशैली की जरूरतों को पूरा करता है। यह को-ब्रांडेड कार्ड दैनिक भुगतानों पर भी रिवार्ड प्रदान करता है।

आसियान-इंडिया आर्टिस्ट कैंप का भव्य समापन

मुंबई (उत्तरशक्ति)। भारत और आसियान देशों के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊँचाई देने वाले तीसरे आसियान-इंडिया आर्टिस्ट कैंप (एआईएसी) का शिलांग में शानदार समापन हुआ। दस दिन तक चले इस शिविर में भारत, आसियान देशों और तिमोर-लेस्ते से आए 21 कलाकारों ने शिलांग की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता से प्रेरित होकर अनूठे चित्र बनाए, जिन्हें त्रिपुरा कासल में प्रदर्शित किया गया। विदेश मंत्रालय और सांस्कृतिक संस्था सहर द्वारा आयोजित यह शिविर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की प्रमुख सांस्कृतिक पहल है। इस अवसर पर विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री श्री पाबित्र मार्गेरिटा और श्री पॉल लिंडो ने शिविर को संबोधित किया। श्री मार्गेरिटा ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट नीति में पीपल फर्स्ट (लोग पहले) दृष्टिकोण का यह शिविर सशक्त उदाहरण है। 2025 को आसियान-भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और यह आयोजन हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत को उजागर करता है। उन्होंने आगे कहा, मेघालय भारत का आसियान से जुड़ने का द्वार है और पूर्वोत्तर भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कलाकारों ने रामायण की भावना को अपनी कला में खूबसूरती से उकेरा है, जिससे भारत-आसियान संबंधों को और गहराई मिली है।

विदेश मंत्रालय की ओर से मैं मेघालय सरकार, सहर टीम और सभी प्रतिभागियों का तीसरे संस्करण को सफल बनाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। सहर के संस्थापक-निदेशक श्री संजीव भार्गव ने कहा, इस शिविर की कल्पना मेरे लिए एक सपना थी और आज यह साकार रूप में हमारे सामने है। इन दस दिनों में कलाकारों ने न सिर्फ एक-दूसरे के विचारों को समझा, बल्कि कलात्मक स्तर पर एक नई उड़ान भी भरी। यह प्रदर्शनी उसी समर्पण, संवाद और रचनात्मक ऊर्जा की झलक है। शिविर के दौरान कलाकारों ने शास्त्रीय नृत्य, स्थानीय संगीत, पारंपरिक हस्तशिल्प, और स्कूली बच्चों के साथ संवाद जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया। यह संवाद रचनात्मकता और सांस्कृतिक समझ के गहरे मेल का प्रतीक बना। अब इन कलाकारों की बनाई पेंटिंग्स को नई दिल्ली और मलेशिया में प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे यह सांस्कृतिक संवाद सीमाओं के पार तक पहुँचेगा। कलाकार यहाँ से नए नजरिये, प्रेरणा और यादों के साथ लौटे हैं-जो कला के जरिए भारत और आसियान देशों के संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाएगा।

कॉलेज में कार स्टंट को लेकर एनएसयूआई ने निकाला विरोध मोर्चा

मुंबई (उत्तरशक्ति)। एमएच साबू सिद्दीकी कॉलेज के ग्राउंड पर विगत दिनों की गई कार स्टंट को लेकर नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के छात्रों ने नेशनल डेलीगेट निखिल रूपारेल तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मुंबई के युवा नेता फुरकान शेख के नेतृत्व में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध मोर्चा निकाला। निखिल रूपारेल ने कहा कि कॉलेज परिसर में कार स्टंट के कारण यहां पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो गया था। कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। उन्होंने कहा छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। कॉलेज प्रशासन को 30 अप्रैल तक का अल्टीमेटम देते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी जांच तथा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो छात्रों की सुरक्षा को लेकर एनएसयूआई चुप नहीं बैठेगा। इस अवसर पर डॉ सुरैना मल्होत्रा, ओवासिस कामिल अंसारी, अल्फाज कुरेशी, नईम खान समेत सैकड़ो की संख्या में एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

शिवसेना ओर से मनपा कार्यालय पर निकाला गया हंडा मोर्चा

मुंबई (उत्तरशक्ति)। शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के आदेश पर मुंबई में जगह जगह पानी के मुद्दे पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की ओर से महानगरपालिका कार्यालय पर जोरदार आंदोलन किया गया। इसी कड़ी में शिवसेना विभाग प्रमुख तुकाराम (सुरेश) कृष्णा पाटिल और विभाग संगठीका श्रीमती प्रज्ञा प्रकाश सकपाल के नेतृत्व में, घाटकोपर पश्चिम और घाटकोपर पूर्व विधानसभा की ओर से मनपा एन विभाग कार्यालय पर

पानी की समस्या को लेकर जोरदार आंदोलन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शिवसैनिकों का यह हंडा मोर्चा घाटकोपर पश्चिम रेलवे स्टेशन, वेलकम होटल से घाटकोपर एन विभाग कार्यालय तक निकाला गया। इस हंडा मोर्चा में घाटकोपर पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों के बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शिवसेना पदाधिकारी, युवा सेना पदाधिकारी उपस्थित थे। बता दें कि दूषित जलापूर्ति, अघोषित जल कटौती, नाला सफाई की समस्या, सड़क मरम्मत की समस्या, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं और जल समस्याओं के खिलाफ, बुधवार को विभाग क्रमांक 8 की ओर से, घाटकोपर पूर्व स्थित मनपा कार्यालय पर शिवसेना नेता, युवा सेना प्रमुख और विधायक आदित्यसाहेब ठाकरे के मार्गदर्शन में यह आंदोलन किया गया। इस अवसर पर शिवसेना विभाग प्रमुख तुकाराम (सुरेश) कृष्णा पाटिल और विभाग संगठीका श्रीमती. प्रज्ञा प्रकाश सकपाल

के साथ विधानसभा प्रमुख सुभाष पवार, संजय चव्हाण, उप विभाग प्रमुख सुनील मोरे, शाखा प्रमुख संजय कदम, चंद्रपाल चंदेलिया, विजय पड़वल, अजीत गुजर सहित बड़ी संख्या में शिवसैनिक और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

इस दौरान शिवसेना की ओर से पानी की किल्लत को लेकर निकाले गए इस हंडा मोर्चा को लेकर शिवसेना का एक शिष्टमंडल विभाग प्रमुख सुरेश पाटील के नेतृत्व में जल विभाग के कार्यकारी अभियंता पाटिल से मिलकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पानी की किल्लत को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिवसैनिक, युवासैनिक और विभाग के नागरिक उपस्थित थे।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से वर्ल्ड मिशन सोसायटी चर्च ऑफ गॉड के स्वयंसेवकों ने की विशेष भेंट

पालघर(उत्तरशक्ति)। पालघर जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित लोक दरबार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोईसर शहर के लोकप्रतिनिधि विलास तरे, शिवसेना युवा नेता विजय पाण्डेय, जिला अध्यक्ष कुंदन संखे तथा उपाध्यक्ष नीलम संखे भी मंच पर मौजूद थे। इस विशेष कार्यक्रम में वर्ल्ड मिशन सोसायटी चर्च ऑफ गॉड के स्वयंसेवकों और कार्यकताओं ने परिवहन मंत्री से भेंट की। उन्होंने पूरे पालघर ज़िले सहित भारतभर में संस्था द्वारा चलाए जा रहे मानव सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी दी, जिनमें प्रमुख रूप से स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, वृद्धाश्रमों में जरूरतमंदों की सहायता, वृक्षारोपण, तथा आपदा की स्थिति में राहत सामग्री का वितरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। मंत्री सरनाईक ने संस्था की इन जनकल्याणकारी गतिविधियों से अत्यधिक प्रभावित होकर उनकी भूरी-भूरी प्रशंसा की। उन्होंने वर्ल्ड मिशन सोसायटी चर्च ऑफ गॉड को पूर्ण सहयोग और समर्थन देने का आश्वासन दिया तथा भविष्य में संस्था के सामाजिक कार्यों में स्वयं उपस्थित रहने की भी बात कही। इस अवसर पर संस्था के स्वयंसेवकों द्वारा परिवहन मंत्री को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया और प्रोत्साहन हेतु प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए गए। परिवहन मंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी स्वयंसेवकों की सराहना की।

उत्तरशक्ति
* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा
*प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।
पत्राचार कार्यालय :
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाफ हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com

स्वामीः शरद फागूराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुदित एवं के-4, रूम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर न्यू समता सहकारी को.ऑ. हां. सोसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजूरमार्ग (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति, समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।
पत्राचार कार्यालयः मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रैक टर्मिनल, डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटाफ हिल, वडाला मुंबई -37, मो.- 9554493941 email ID- uttarshaktinews@gmail.com

इन्दिरा गांधी स्टेडियम में निमार्णाधीन सिन्थेटिक रनिंग ट्रैक, मल्टीपरपज हाल, तरणताल का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र के द्वारा इन्दिरा गांधी स्पोर्टस स्टेडियम सिद्दीकपुर में निमार्णाधीन सिन्थेटिक रनिंग ट्रैक, मल्टीपरपज हाल, तरणताल के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण करते हुए निर्माण कार्यों की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। सिन्थेटिक रनिंग टैक के निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि 01 महीने के भीतर कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। मल्टीपरपज हाल निर्माण के निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि 02 महीने के भीतर कार्य पूर्ण हो जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, इसके साथ ही निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे, जिससे जनपद के खिलाडी.सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सके। जिलाधिकारी ने मौके पर कार्यरत श्रमिकों से संवाद करते हुए उनके बीमा एवं श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में जानकारी ली और निर्देशित किया कि जिन श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन नही हुआ है उनका श्रम विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें।

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने श्रमिकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजाना के लाभों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में दुर्घटना होने आदि की स्थिति में यह बीमा उपयोगी सिद्ध होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में खेलों की सुविधाओं को बढाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को अन्य जनपदों में नही जाना पडेगा उन्हे जनपद में ही खेल की सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।इस अवसर पर कार्यदाई संस्था के प्रतिनिधिगण, क्रीड़ा विभाग के कार्यालय सहायक सुजीत विश्वकर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे।

डॉ.हरेंद्र देव सिंह को मिला 'मेडिकस एलिट ऑनर रोल' सम्मान

एक दिन में 25,000 से ज्यादा लोगों की शुगर जांच कर बनाया विश्व रिकॉर्ड

जौनपुर(उत्तरशक्ति)। जिले के कृष्णा हार्ट केयर कैथलैब के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉ.हरेंद्र देव सिंह को 'मेडिकस एलिट ऑनर रोल' से राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम डॉ.बृजेश पाठक के हाथों सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमतीनगर में हुए क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा की राष्ट्रीय कांफ्रेंस में चिकित्सा क्षेत्र का एक ऐतिहासिक क्षण था।जब इस सम्मेलन में देश-विदेश के डॉक्टरों और चिकित्सा पदाधिकारियों की मौजूदगी में डॉ. हरेंद्र देव सिंह को यह सम्मान मिला तो जिले के लोग भी काफी गर्व महसूस किये।

लखनऊ से लौट कर आए शहर के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ एचडी सिंह ने मंगलवार को जेसीज स्थित अपने संस्थान पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि यह सम्मान उन्हें उनके अद्वितीय और ऐतिहासिक कार्य के लिए प्रदान किया गया है। जिसमें उन्होंने एक ही दिन में लगभग 25,000 लोगों की शुगर जांच कर उनका पूरा डेटा डिजिटल माध्यम (गूगल शीट) पर सुरक्षित रूप से दर्ज किया। यह अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को चुनौती देने योग्य बताया जा रहा है।सिंह की इस उपलब्धि पर अकेले सिर्फ जौनपुर ही नहीं पूरा पूर्वांचल गर्व महसूस कर रहा है।इससे पहले डॉ. हरेंद्र देव सिंह को उनके इस असाधारण योगदान के लिए आरएसएसडीएल, इनर सर्कल यूपीसीएल समेत अन्य विभिन्न डॉक्टरों की राष्ट्रीय एसोसिएशनों द्वारा झाँसी, आगरा, गोवा, वाराणसी और हरिद्वार में सम्मानित किया जा चुका है। यह उपलब्धि न सिर्फ चिकित्सा

विज्ञान में एक मिसाल है, बल्कि एक डॉक्टर के समर्पण, सेवा और सामूहिक प्रयासों की प्रेरक कहानी भी है।

विश्व स्तर पर पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं डॉ.एचडी सिंह

जौनपुर। शहर के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डा.एचडी सिंह को इसके पहले भी संयुक्त राष्ट्र सऊदी अरब और दुबई में पुरस्कृत किया जा चुका है।एम.डी. (मेडिसिन) डी.आई.पी.कार्ड, डी.एम.ए.एम., ई.ए.एस.सी एफ.आई. यश एच, ए.सी सी और ई. एस.सी ए.सी.सी (यू.एस.ए) आई.एम.सी.आई.आर (यूरोप) एम.सी.आई (भारत) के सदस्य कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष आई.एम.ए अध्यक्ष द्वारा विशेष प्रशंसा पुरस्कार दिया जा चुका है।वर्ष 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा स्टेमी हीरो पुरस्कार और वर्ष 2022 में राष्ट्रीय आई.एम.ए अध्यक्ष द्वारा उत्कृष्ट और विशिष्ट सेवाओं के लिए डॉ. ए.के.एन. सिन्हा पुरस्कार मिल चुका है।

आई.एस.एम.एन स्वास्थ्य देखभाल उत्कृष्टता पुरस्कार, डब्ल्यू.सी.एम.एन (वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ मेडिकल फूड एंड न्यूट्रिशन) द्वारा स्वास्थ्य (दुबई में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार) 2023, भारत के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आइकॉन्स ऑफ हेल्थ केयर अवार्ड और इंडिया टुडे मैगजीन 2023 में स्थान मिला, स्वास्थ्य देखभाल में अग्रणीराज्यसभा के उपसभापति, आउटलुक मैगजीन 2023 में स्थान मिला। कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में रोकथाम और अनुसंधान के क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल, रिकॉर्ड ब्लड शुगर स्क्रीनिंग (जाहिर तौर पर आज तक 1.5 लाख), ए.एच.जे बी.एम.जे और जे.ए.पी.आई. के लिए हार्ट फेल्योर और डिस्लिपिडेमिया में विभिन्न प्रकाशन हो चुका है।

बदलापुरः ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज

धर्मेंद्र कुमार शर्मा

बदलापुर,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। विकासखंड के समाजवादी पार्टी की ब्लॉक प्रमुख आशा देवी पत्नी अरुण कुमार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव कोरम अधूरा रहने के चलते निरस्त कर दिया गया। यह प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत सदस्य अमित शर्मा पुत्र शोभनाथ (वार्ड संख्या-41) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव पर विचार हेतु बुधवार को सुबह 11 बजे क्षेत्र पंचायत कार्यालय बदलापुर में बैठक आहूत की गई थी, जिसकी अध्यक्षता नामित अधिकारी द्वारा की गई। बैठक निर्धारित समयानुसार दोपहर 1 बजे तक चली, लेकिन सदस्यों की अपेक्षित उपस्थिति न होने के कारण प्रस्ताव पर मतदान नहीं हो सका।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में कुल 105 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से केवल 48 सदस्य ही उपस्थित रहे, जबकि प्रस्ताव पर मतदान के लिए दो-तिहाई यानी कम से कम 70 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य थी।कोरम पूरा न होने के कारण प्रस्ताव स्वतः निरस्त माना गया। जिसकी जानकारी बदलापुर की उप जिलाधिकारी डॉक्टर योगिता सिंह के द्वारा दी गई।इस घटनाक्रम के बाद ब्लॉक प्रमुख आशा यादव को फिलहाल बड़ी राजनीतिक राहत मिली है। वहीं, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ब्लॉक परिसर में दिनभर तनाव का माहौल बना रहा, जिसे देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल की तैनाती की थी। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच बैठक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। स्थानीय राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को लेकर चचाओं का दौर जारी है।

शाहगंज पुलिस ने अपहरण, बलात्कार सहित पाक्सो एक्ट के वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार

शाहगंज,जौनपुर(उत्तरशक्ति)। डा0 कौस्तुभ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे ।अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक नगर जौनपुर आयुष श्रीवास्तव एवं क्षेत्राधिकारी शाहगंज अजीत सिंह चौहान के निर्देशन व निकट पर्वेक्षण में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 227/2024 धारा 137(2), 87, 64 भारतीय न्याय संहिता 2023 व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित आरोपी सर्वेश कुमार उर्फ करिया पुत्र विरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम भदसर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 16.04.2025 को समय 09 :35 बजे थाना गेट शाहगंज से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सम्बन्धित न्यायालय भेजा जा रहा है।

सेना के जवान का अन्तिम दर्शन को उमड़े ग्रामीण, नम आँखों से दी गई विदाई

जौनपुर(उत्तरशक्ति)। अरुणाचल प्रदेश में तैनात सेना के जवान सौरभ यादव का निधन हृदयाघात से हो गया। उनका पार्थिव शरीर बुधवार को उनके पैतृक गांव सिकरारा पहुंचा। सौरभ यादव सिकरारा (इटहवां) गांव के लालबहादुर यादव के छोटे पुत्र थे। रविवार को परिजनों को फोन पर उनकी मृत्यु की सूचना मिली। इस दुखद समाचार से पूरे गांव में शोक छा गया। सेना के अधिकारियों ने फौजी के पिता को सूचित किया कि वे पार्थिव शरीर को विमान से लाएंगे। मंगलवार को पार्थिव शरीर बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचा। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सुबह उन्हें गांव लाया गया। जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा रहा। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। सिकरारा चौराहे पर ग्रामीणों ने एम्बुलेंस के बजाय सेना के वाहन में शव न लाए जाने पर विरोध जताया। सीओ सदर परमानंद कुशवाहा और परिजनों के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। स्थानीय लोगों ने अपने गांव के वीर सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

मछलीशहर के बसिरहा गांव के मछुआरे घुरहू बिंद की पाकिस्तान की कराची जेल में मौत

जौनपुर(उत्तरशक्ति)। मछलीशहर कोतवाली क्षेत्र के बसिरहा गांव के मछुआरे घुरहू बिंद की पाकिस्तान की कराची जेल में मौत हो गई है। मंगलवार को मत्स्य विभाग की निरीक्षक ने घर पहुंचकर परिजनों को बताया कि घुरहू ने जेल में आत्महत्या कर ली है। वह पांच वर्ष से पाकिस्तान की जेल में बंद थे।ग्राम प्रधान मृत्युंजय बिंद ने बताया कि 48 वर्षीय घुरहू बिंद (गुजरात के ओखा बंदरगाह के पास मछली पकड़ते थे। वर्ष 2020 में देश की जल सीमा पार कर मछली पकड़ने के आरोप में पाकिस्तानी तटरक्षकों ने उन्हें पकड़ लिया था और जेल में बंद कर दिया था। परिवार के लोगों ने भारत सरकार से संपर्क किया, मगर घुरहू को जेल से छुड़वाने में सफलता नहीं मिली। मंगलवार को घुरहू के घर मत्स्य विभाग की निरीक्षक संभाषी त्रिपाठी पहुंचीं। उन्होंने बताया कि मत्स्य निदेशालय से दूरभाष पर घुरहु बिंद की मौत की जानकारी मिली है। उनको मौके पर सत्यापन के लिए भेजा गया है। 16 अप्रैल को बाघा बॉर्डर और वहां से 17 अप्रैल को घुरहू का शव घर पहुंचने की उम्मीद है। इस मौके पर ग्राम प्रधान व अन्य लोग मौजूद रहे।

विभिन्न मामलों में 12 आरोपी गिरफ्तार

जौनपुर(उत्तरशक्ति)। पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे। विशेष

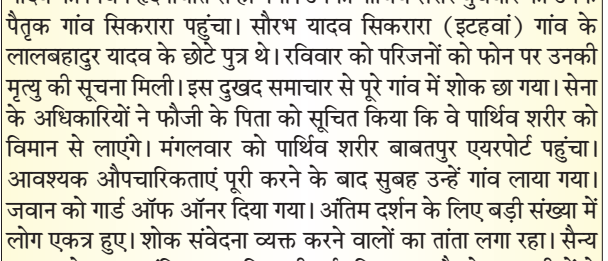

अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) के दिशा निर्देशन व क्षेत्राधिकारी बदलापुर जौनपुर के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष थाना सुजानगंज जौनपुर के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक-16.04.2025 को 12 नफर अभियुक्त/ अभियुक्ता 1.अवनीश तिवारी पुत्र छविनाथ तिवारी उम्र करीब 32 वर्ष 2. दुर्गेश सिंह पुत्र रामबहादुर सिंह 3. अनिल सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह समस्त निवासीगम ग्राम करौरा थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर 4.अविनाश बिन्द पुत्र मोतीलाल बिन्द 5. धर्मेन्द्र बिन्द पुत्र स्व0 केदारनाथ बिन्द 6. मोतीलाल बिन्द पुत्र स्व0 केदारनाथ 7.संगीता बिन्द पत्नी धर्मेन्द्र बिन्द व द्वितीय पक्ष के 8.दिनेश कुमार बिन्द पुत्र स्व0 राम केदार बिन्द 9. प्रमीला देवी पत्नी दिनेश कुमार बिन्द निवासीगण ग्राम डीहगडवार थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर 10.विनोद सरोज पुत्र बुद्धिराम सरोज व द्वितीय पक्ष के 11. विनोद सरोज पुत्र दयाशंकर सरोज निवासीगम ग्राम गिड़हुली थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर 12.मुन्नीलाल पुत्र स्व0 छोटू राम निवासी ग्राम पतहना थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर का चालान धारा अन्तर्गत 126/135/170 बीएनएसएस की कार्यवाही किया गया।

जौनपुर की नई मुख्य विकास अधिकारी बनीं मृणाली जोशी, साईं सीलम तेजा प्रयागराज स्थानांतरित

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिले को नई मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) मिल गई हैं। 2021 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी मृणाली जोशी को जौनपुर का नया सीडीओ नियुक्त किया गया है।वे अब तक गोरखपुर में संयुक्त मजिस्ट्रेट और एसडीएम सदर के पद पर कार्यरत थीं।मृणाली जोशी पुणे, महाराष्ट्र की निवासी हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक और लोक प्रशासन (पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन) में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है। उनकी प्रशासनिक सेवा की शुरूआत अलीगढ़ में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद से हुई थी। इसके बाद शासन ने उन्हें गोरखपुर भेजा, जहां उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया।गोरखपुर में कार्यकाल के दौरान मृणाली जोशी ने मुख्यमंत्री की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीन पर सफलतापूर्वक लागू किया।

उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर योजनाओं को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ाया। उनकी कार्यशैली की प्रशंसा शासन स्तर पर भी की गई। नवीन तैनाती पर मृणाली जोशी ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि कार्यालय में आने वाले प्रत्येक पीड़ित को न्याय मिले और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचे। वहीं, अब तक जौनपुर में सीडीओ पद पर कार्यरत साईं सीलम तेजा का स्थानांतरण नगर निगम प्रयागराज में नगर आयुक्त के पद पर कर दिया गया है। उनके कार्यकाल में भी कई विकास योजनाएं जौनपुर में प्रभावी रूप से चलाई गईं।

धूमधाम से मनायी गयी भारत रत्न बीआर अंबेडकर की जयंती

केराकत,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। केराकत विकासखंड क्षेत्र के सुल्तानपुर ग्राम में मंगलवार को भारतीय संविधान के पुरोधर भारत रत्न डा.बी आर अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूम धाम के साथ मनाया गया ।कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर आगन्तुक अतिथियों में मास्टर नरायण, रामरतन, सुभास, निवर्तमान प्रधान ओमप्रकाश, जिलपंचायत सदस्य प्रतिनिधि पप्पू सरोज, बच्चेलाल निराला, डा.जीतराम भारतीय, पूर्व प्रधान गोपाल शर्मा, आफताब आलम, असलम आदि प्रमुख ने भारत रत्न की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने अपने विचार व्यक्त कर भाव भरी श्रद्धा सुमन अर्पित कियें ।कार्यक्रम की अध्यक्षता मास्टर नरायण व संचालन कार्यक्रम के आयोजक निवर्तमान प्रधान सुल्तानपुर ओमप्रकाश द्वारा किया गया।

मुंगराबादशाहपुर में वार्षिकोत्सव, प्रवेशोत्सव, स्मार्ट क्लास का उद्घाटन

सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह का किया गया आयोजन

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। खण्ड शिक्षा अधिकारी मुंगराबादशाहपुर डॉ.अविनाश सिंह के द्वारा प्राथमिक विद्यालय रामपुर गजाधर, मुंगराबादशाहपुर में वार्षिकोत्सव, प्रवेशोत्सव, स्मार्ट क्लास उद्घाटन एवं सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं अतिथियो का माल्यार्पण, स्मृति चिह्न एवं अंगवस्त्र देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ० गोरखनाथ पटेल द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। विद्यालय के छात्र/छात्राओं द्वारा एकांकी, लोकनृत्य एवं विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण किया गया। बी0 एस0 ए0 ने कहा कि विकासखण्ड मुंगराबादशाहपुर के किसी भी बस्ती/मजरे का 6-14 वर्ष का कोई भी बच्चा नामांकन से छूटने न पाये। सभी अध्यापकों को अभिभावकों से संपर्क करने के साथ ही बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर दो सप्ताह तक चलने वाले हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम हेतु निर्देशित किया गया।कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक अजीत पटेल एवं विद्यालय स्टाफ की प्रशंसा की गई।कार्यक्रम में खण्ड विकास अधिकारी मुंगराबादशाहपुर सूर्यकांत पाण्डेय, खण्ड शिक्षा अधिकारी जमानियां, जनपद गाजीपुर सुरेन्द्र सिंह पटेल, खण्ड विकास अधिकारी मछलीशहर अमरदीप जायसवाल, महराजगंज रमेश चंद्र पटेल, सिकरारा अजीत सिंह, ग्राम प्रधान श्रीमती शकुंतला देवी, सेवानिवृत्त शिक्षक राजीव रत्नम तिवारी, बाबूराम यादव एवं दिनेश चंद्र त्रिपाठी उपस्थित रहे। संचालन सुमन गुप्ता एवं उपेन्द्र सिंह द्वारा किया गया।कार्यक्रम में विकासखण्ड के शिक्षक/शिक्षिकाएं एवं भारी संख्या में महिला/ पुरुष अभिभावक उपस्थित रहे।

नवनिर्मित वाल वाटिका भवन का उद्घाटन

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। पीएम श्री विद्यालय पर वहां के प्रधानाध्यापक रामपाल व समस्त शिक्षकों के सहयोग से वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया।इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक विधानसभा बादलपुर रमेश चंद्र मिश्रा जी व विशिष्ट अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ0 गोरखनाथ पटेल के कर कमलो से नवनिर्मित वाल वाटिका भवन का उद्घाटन किया गया।विद्यालय के बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। माननीय मुख्य अतिथि जी द्वारा विद्यालय में शिक्षकों द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता हेतु किए जा रहे प्रयास व मिशन प्रेरणा तथा कायाकल्प के तहत विद्यालय में किया जा रहे कार्यों की प्रशंसा की गई साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों को अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए समय से विद्यालय में पहुंचाने हेतु अपील की गई।कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र पटेल द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया गया। इस अवसर पर अवकाश प्राप्त शिक्षक अशोक कुमार सिंह, रमाकांत, राधेश्याम, लालमणि यादव, केशव, चंद्रप्रकाश आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक अध्यक्ष उमा नाथ यादव ने किया।

जल बचाने की मुहिम में जन भागीदारी जरूरी: प्रो.एम.पी.सिंह

पीयू में जल संचयन-जन भागीदारी के अंतर्गत विशेष व्याख्यान का हुआ आयोजन

जौनपुर(उत्तरशक्ति)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग द्वारा जल संचयन-जन भागीदारी के अंतर्गत विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। विशेष व्याख्यान में बतौर मुख्य वक्ता इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रो. एम.पी सिंह ने जल के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जल बचाने की मुहिम में जन भागीदारी जरूरी है। जल को बचाने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है।उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष पहले की तुलना में कम वर्षा हो रही है ऐसी स्थिति में हमें कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण हेतु कार्य करने की जरूरत है। वर्षा ऋतु में आने वाले जल के संरक्षण और उनके सतत प्रबंधन के साथ-साथ भूगर्भ जल का कम से कम दोहन करना होगा। प्रो.सिंह ने बताया कि भारत मे प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1513 क्यूबिक मीटर संकट को दशार्ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाला समय बहुत ही भयावह होगा। आपदाओं का सामना करना पड़ेगा।नदियों का जलस्तर भी घटेगा। इससे कृषि और पेयजल प्रभावित होगा इसलिए हमें निरंतर जल संचयन एवं वृक्षारोपण करने की जरूरत है। इन प्रयासों से हम भविष्य की समस्याओं से निजात पा सकेंगे। इस अवसर पर प्रो.रामनारायण ने कहा कि वर्षा जल संरक्षण से भूजल स्तर को बढ़ाने के उपायों को सुझाया. कहा कि जल स्त्रोतों के संरक्षण से प्रकृति का संरक्षण होगा। इस अवसर पर जल संचयन- जन भागीदारी के नोडल अधिकारी, पर्यावरण विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. विवेक कुमार पाण्डेय द्वारा अतिथियों का स्वागत करते हुए विषय प्रवर्तन किया गया। इस अवसर पर विज्ञान संकाय के डॉ. एस.पी. तिवारी, डॉ. दीपक कुमार समेत अन्य उपस्थित रहे। धन्यवाद् ज्ञापन छात्रा वर्षा यादव एवं कार्यक्रम का संचालन अंकिता यादव ने किया।

रामपुर विद्युत उपकेंद्र के एसएसओ का नर्तकी संग डांस करते वीडियो वायरल, फिर उठे सवाल

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जनपद के रामपुर विद्युत उपकेंद्र में तैनात एसएसओ (सब स्टेशन ऑपरेटर) अविनाश यादव एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार उनका एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक नर्तकी के साथ मंच पर ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, वीडियो में वे नर्तकी पर पैसे उड़ाते भी दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो रामपुर बाजार में आयोजित एक निजी पार्टी का है, जहां अविनाश यादव ने ड्यूटी के समय पहुंचकर नाच-गाने का आनंद लिया।स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि एसएसओ मंच पर नशे की हालत में थे और उन्होंने अपने पद की गरिमा को ताक पर रखकर सार्वजनिक रूप से नाचने का प्रदर्शन किया। इस वीडियो के वायरल होते ही विद्युत विभाग में एक बार फिर हड़कंप मच गया है।गौरतलब है कि इससे पहले भी अविनाश यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे रामपुर विद्युत उपकेंद्र के अंदर शराब और कबाब की दावत उड़ाते नजर आ रहे थे। उस समय एसडीओ मुरलीधर मौर्य ने उक्त वीडियो को पुराना बताते हुए किसी भी प्रकार की कार्रवाई से इनकार कर दिया था। लेकिन अब नर्तकी संग मंच पर डांस का नया वीडियो सामने आने के बाद विभागीय लापरवाही और अनुशासनहीनता को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं।स्थानीय जनता का कहना है कि विभाग द्वारा समय रहते कोई सख्त कदम न उठाए जाने के कारण एसएसओ के हौसले बुलंद हैं। ड्यूटी के दौरान ऐसी हरकतें न केवल विभाग की छवि को धूमिल कर रही हैं, बल्कि आम जनता के विश्वास को भी चोट पहुँचा रही हैं।अब देखना यह है कि विद्युत विभाग इस ताजा वायरल वीडियो के बाद क्या कोई ठोस कार्रवाई करता है या फिर यह मामला भी पुराने वीडियो की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।

डॉ.शरद सिंह देवदूत वानर सेना का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। पूर्वी उत्तर प्रदेश जौनपुर से डॉक्टर शरद सिंह लंबे समय से देवदूत वानर सेना से जुड़े है। संगठन में प्रत्येक जिम्मेदारी को इन्होंने सदा सराहनीय तरीके से पूरा किया। अनेकों मुहिम को सफल बनाने में इनका महत्वपुर योगदान भी रहा है। सचिव पद से लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष के पद तक का सफर सदा निस्वार्थ कार्य करते हुए इन्हें प्राप्त हुआ। देवदूत वानर सेना के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आज डॉ. श्री शरद सिंह को आखिरकार वह महत्वपूर्ण पदभार सौंपा गया, जो पिछले काफी समय से रिक्त था। यह घोषणा संगठन के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर की गई, जिसने इस पद की गरिमा को और भी बढ़ा दिया। डॉ. शरद सिंह लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए हैं और वानर सेना के एक शांत, परिश्रमी सिपाही की तरह उन्होंने हमेशा पृष्ठभूमि में रहकर अथक कार्य किया है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सामाजिक अभियानों और मिशनों में सक्रिय भागीदारी निभाई है तथा संगठन के सिद्धांतों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया है।संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस निर्णय को विचारशील एवं दूरदर्शी बताया है। यह न केवल डॉ. शरद सिंह की प्रतिबद्धता और सेवा को मान्यता देता है, बल्कि यह भी संकेत करता है कि संगठन अब भविष्य की ओर सशक्त तौर पर आगे बढ़ रहा है। सभी की निगाहें अब डॉ. शरद सिंह के नेतृत्व पर टिकी हैं और उन्हें विश्वास है कि वे इस मानवीय पहल वाले देवदूत वानर सेना संगठन को प्रदेश से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। संगठन के वरिष्ठ सदस्यों, सहयोगियों एवं समर्पित देवदूतों ने उन्हें इस नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।

ट्रेन पलटाने की साजिश से रेलवे लाइन पर रखा मिला लकड़ी का टुकड़ा

लखनऊ (उत्तरशक्ति)। रहीमाबाद में दिलावरनगर के पास अराजकतत्वों ने ट्रेन की पटरी पर लकड़ी का गुटका रख दिया। गाड़ी संख्या 05577 यूपी लोको से लकड़ी का गुटका टकरा गया। बुधवार को स्टेशन मास्टर रहीमाबाद ने आरपीएफ को मामले की सूचना दी। आरपीएफ की ओर से रहीमाबाद थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। इस घटना के पीछे साजिश की आशंका जताई जा रही है। पुलिस की कई टीमें मामले की जांच कर रही हैं। आरपीएफ में तैनात राजेश रंजन के मुताबिक जानकारी मिलने पर वह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान वहां ट्रेन की पटरी के उत्तर दिशा में दोनों लाइनों के बीच एक लकड़ी का सूखा तना रखा था। इसकी लंबाई करीब ढाई फीट एवं मोटाई लगभग छह इंच थी। यही नहीं आम के पेड़ की हरी डालियां एवं एक नारंगी रंग का कपड़ा भी रखा था, जिस पर राम नाम छपा था। टीम ने डीएन लाइन चेक किया तो कुछ दूरी पर आम की और लकड़ियां भी रखी हुई मिलीं। टीम ने फौरन सारी लकड़ियों को हटाया। इसके बाद अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई। आरोप है कि रेलवे लाइन पर लकड़ी के तने को गाड़ी संख्या-05577 के लोको पायलट ने हटा दिया अन्यथा जान माल का नुकसान हो सकता था। उधर, लकड़ियों को हटाने के दौरान सभी ट्रेनों को रोक दिया गया था। काफी देर तक बड़ी संख्या में ट्रेनें प्रभावित हुईं। इसकी वजह से यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण की जानकारी खुफिया एजेंसियों को दी गई है। बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। इसके पहले भी दिलावर नगर में ट्रेन की पटरियों पर लकड़ी का तना रखा गया था। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। यही नहीं, एटीएस समेत कई एजेंसियों ने प्रकरण की जांच की थी। तब माना जा रहा था कि किसी ने ट्रेन पलटाने की साजिश रची है।

फर्जी दस्तावेज लगाकर एक करोड़ का लोन हड़पा

लखनऊ (उत्तरशक्ति)। हसनगंज की डालीगंज स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में फर्जी दस्तावेज लगाकर 11 लोगों पर 1 करोड़ 6 लाख 15 हजार एक्सप्रेस क्रेडिट लोन हासिल करने का आरोप लगा है। इस मामले में क्षेत्रीय प्रबंधक विपिन सिंह ने सभी 11 लोन धारकों, तीन बिचौलियों, तत्कालीन शाखा प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर और मैनेजर बैंकिंग ऑपरेशन के खिलाफ हसनगंज थाने में सोमवार को केस दर्ज कराया है। विपिन सिंह के अनुसार 15 जुलाई 2023 से 30 जनवरी 2024 के बीच 11 खातेदारों को एक्सप्रेस क्रेडिट लोन पास किया गया। इस अवधि के दौरान शाखा के कारोबार में आश्चर्यजनक वृद्धि मिली। शक होने पर जांच की गई तो पता चला कि नियम को दरकिनार करते हुए फर्जी दस्तावेज के सहारे उक्त 11 खाताधारकों को 1 करोड़ 6 लाख 15 हजार का लोन पास किया गया था। जांच में सामने आया कि लोन हासिल करने के लिए वेतन पर्ची, फर्जी केवाईसी, फर्जी जन्मतिथि का प्रमाण पत्र लगाया गया था। इस फजीवाड़े में बैंक के कुछ कर्मचारी और कुछ बिचौलिए भी शामिल रहे। जांच पूरी हो जाने के बाद क्षेत्रीय प्रबंधक विपिन सिंह ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की थी। एफआईआर में तत्कालीन शाखा प्रबंधक संजीव त्रिपाठी, फील्ड ऑफिसर अमृता चटर्जी और मैनेजर बैंकिंग ऑपरेशन अमित जैन नामजद हैं।

मुठभेड़ मे पशु तस्कर गिरफ्तार, असलहा बरामद

आजमगढ़ (उत्तरशक्ति)। आजमगढ़ के थाना तहबरपुर क्षेत्र में बीती रात को पुलिस और गो-तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में अंतर्जनपदीय गो-तस्कर रोहित यादव घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई में ट्रक पर लदे 20 प्रतिबंधित पशु बरामद किए गए, साथ ही अवैध असलहा और कारतूस भी जब्त किए गए। घायल बदमाश का दूसरा साथी आबिद अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। एसएसपी हेमराज मीना ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर चेकिंग के दौरान ट्रक संख्या यूपी 63टी 8818 को रोका। ट्रक चालक रोहित यादव निवासी कोहड़ा, थाना शाहगंज, जौनपुर और उसका साथी आबिद मौके से भाग निकले थे। ट्रक से 20 प्रतिबंधित पशु बरामद हुए, जिसके आधार पर थाना तहबरपुर में उप्र गौहत्या निवारण अधिनियम और 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान को रात में पुलिस को सूचना मिली कि रोहित यादव और उसका साथी ग्राम करियावर के पास एक खंडहर में छिपे हैं। पुलिस ने खंडहर को घेर लिया, तभी रोहित ने पुलिस पर फायरिंग की, जो प्रभारी निरीक्षक के दाहिने कान के पास से निकली। आत्मरक्षा में पुलिस की नियंत्रित फायरिंग में रोहित के दाहिने पैर में गोली लगी। उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तहबरपुर भेजा गया। उसके कब्जे से एक देशी तमंचा 315 बोर और कारतूस बरामद हुआ। अंधेरे का फायदा उठाकर उसका दूसरा साथी आबिद फरार हो गया। पूछताछ में रोहित ने बताया कि वह और आबिद राजस्थान के भाटों से गाय और बैल खरीदकर बिहार के सिवान जिले के कर्बला में व्यापारियों को बेचते हैं। रोहित यादव का आपराधिक इतिहास लंबा है, जिसमें आजमगढ़, जौनपुर, उन्नाव, गोरखपुर, फतेहपुर, प्रयागराज और अमेठी में गौ-तस्करी, गैंगस्टर एक्ट, हत्या का प्रयास और अन्य धाराओं में 13 मामले दर्ज हैं।

अधूरा नाली निर्माण से जलभराव होने से परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन

अहरौला। विकासखंड अहरौला के गांव मेंहदवारा में पिछले तीन वर्षों से नाली निर्माण न होने के कारण राजभर और पाल समुदाय के 50 परिवार कीचड़ और गंदे पानी से होकर गुजरने के लिए मजबूर हैं। गांव की महिलाओं ने मंगलवार को जलजमाव में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं में इंद्रावती देवी, संत राजी, हिमरावती, इस्रावती, उर्मिला, प्रमिला, शकुंतला आदि शामिल थीं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नाली निर्माण की समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में सैकड़ों ग्रामीण शाहपुर बाजार में अहरौला-बूढ़नपुर मार्ग जाम करेंगे और धरना-प्रदर्शन करेंगे। बस्ती के बीच में जगदीश के घर से सिधारी के घर तक इंटरलॉकिंग रोड के साथ ह्यूम पाइप नाली बनी है, लेकिन यह नाली सरकारी पोखरी तक मात्र 15 मीटर की दूरी तक नहीं पहुंच पाई है। गांव के कुछ व्यक्तियों ने नाली निर्माण का विरोध किए जाने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इससे बस्ती में गंदा पानी और कीचड़ जमा हो रहा है, जिससे दुर्गंध और संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। ग्रामीणों ने इस अधूरी नाली को पूरा करने की मांग थाना दिवस, तहसील दिवस, पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर, एमएलसी रामसूरत राजभर और अहरौला एसओ तक पहुंचाई है। ग्राम प्रधान पति रामनरायन ने बताया कि एसडीएम और तहसीलदार ने नाली निर्माण की स्वीकृति दे दी है। यदि कोई निर्माण में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, ग्रामीणों का आरोप है कि स्वीकृति के बावजूद ग्राम प्रधान इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। इस संबंध में एसडीएम बुढ़नपुर सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी ने कहा कि ग्राम प्रधान के प्रार्थना पत्र पर नाली निर्माण का आदेश दिया गया है।

निजीकरण से बिजली के दाम में हो जायेगी तीन गुना वृद्धि : नीरज बिन्द

सुरेश गांधी

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को भी राज्य विधुत परिषद जूनियर इंजीनियर संघठन वाराणसी क्षेत्र के प्रथम व द्वितीय के मुख्य अभियंता वाराणसी कार्यालय के प्रांगण में दो दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने निर्णय लिया कि यदि बिजलीकर्मियों का उत्पीड़न किया गया तो न सिर्फ देशव्यापी आंदोलन होगा, बल्कि समिति जनता के बीच निजीकरण की खामियां को उजागर करेगी। साथ ही बताया गया कि निजीकरण होने से किसानों और आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली के दाम कम से कम तीन गुना बढ़ जाएंगे। खास यह है कि इस विधुत

सुधार गोष्ठी में वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली के समस्त अवर अभियंता व प्रोन्नत अभियंता मौजूद रहे। गोष्ठी में बताया गया कि बिजली निगम के अभियंता और कर्मचारी निजीकरण के दुष्प्रभावों से जनता को अवगत कराने के लिए आज से अभियान चलाएंगे। वे उपभोक्ताओं को निजीकरण के नुकसान और बिलों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी देंगे। वे लोगों तक पहुंचकर उन्हें बताएंगे कि कैसे बिजली कंपनियों का निजीकरण उपभोक्ताओं के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और इससे उनके बिजली बिलों पर क्या असर पड़ेगा। इसके साथ ही कर्मचारियों ने इस मुद्दे पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। सभा को सम्बोधित करते हुए पूर्वांचल सचिव नीरज बिन्द द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा तय किये गये यार्ड-स्टिक के अनुसार या मानक के अनुसार संसाधन एवं मानव बल के उपलब्ध न होने से एवं प्रबधन के द्वारा तरह-तरह के फिजूल खर्च पर नियंत्रण न करने से राजस्व गेप में वृद्धि हुयी है। समय रहते यदि इन सुधार कार्यक्रम चला कर सरकारी तंत्र में रखते हुये भी निजी व्यवस्था की अपेक्षा बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विधुत विभाग निजीकरण से किसान, कर्मचारीयों और छात्रों का भविष्य अंधकार में ढकेला जा रहा है। साथ ही एक सामाजिक असंतुलन उत्पन्न करने का प्रयास किया जा है। उन्होंने बताया कि निजीकरण से उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, रोजगार की अनिश्चितता बढ़ेगी और सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होगी। निजी कंपनियां केवल अपने लाभ के बारे में सोचती हैं, जबकि सरकार की जिम्मेदारी जनता का कल्याण करना है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि निजीकरण के विरोध में आंदोलन कर रहे बिजलीकर्मियों का उत्पीड़न किया गया, तो पूरे देश के करोड़ों कर्मचारी आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जबकि कर्मचारी निर्बाध विधुत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये जनता को सस्ती व सुविधाजानक बिजली उपलब्ध कराये जाने के लिये संकल्पबद्ध है।

वक्ताओ की कड़ी मे केंद्रीय उपमहासचिव दीपक गुप्ता ने बताया कि ऊर्जा प्रबंधन पूजीपतियों को लाभ पहुंचाने के मंशा के अनुरूप कार्य कर रहा है, विभाग के बेहतरी के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है। सभा अध्यक्ष पंकज जायसवाल ने बताया कि निजीकरण किसी भी दशा मे स्वीकार नहीं किया जायेगा, चाहे इसके लिए केंद्र को जिस स्तर तक लड़ाई लड़नी पड़े लड़ा जायेगा। साथ ही प्रबंधन को चेतावनी दिया कि जल्द से जल्द निजीकरण की प्रक्रिया पर विराम लगाया जाये अन्यथा कि स्थिति में संगठन वृहद स्तर पर आंदोलन को बाध्य होगा। सभा में मौजूद सभी सदस्यों ने एक स्वर मे निजीकरण का विरोध किया तथा विभाग को निजीकरण से बचाने एवं बेहतर विधुत उपभोक्ता सेवा देने का संकल्प लिया। साथ ही निजीकरण के विरोध में किसी भी स्तर तक विरोध करने का निर्णय लिया गया।

वडाला भक्ति पार्क क्रिकेट क्लब की टीम अब नजर आएगी ब्लू जर्सी एवं ब्लू कैप में

मुंबई (उत्तरशक्ति)। गत दिवस वडाला भक्ति पार्क क्रिकेट क्लब की टीम ने 2025 की न्यू जर्सी एवं ब्लू कैप लॉन्च किया है। मुंबई के भक्ति पार्क ग्राउंड में मुंबई के सायन, वडाला, एंटॉप हिल,के युवा खिलाड़ियों द्वारा एक सशक्त और मजबूत टीम बनाई गई है, जो लगभग 11 वर्षों से मुंबई के आसपास न्यू मुंबई, नालासोपारा, विरार, पालघर, भिवंडी जैसे एरिया मे डबल्यू बी सी क्रिकेट टीम का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है। टीम के अध्यक्ष डॉ शेषधर बिंद ने बताया कि यह सशक्त और मजबूत युवा क्रिकेट खिलाड़ियों की टीम है जो मुंबई के आसपास एरिया में अच्छा प्रदर्शन के रूप में जानी जाती है। टीम में अध्यक्ष डॉ शेषधर बिंद ,उपाध्यक्ष हसन शेख, सेक्रेटरी कमलेश सिंह, उप सेक्रेटरी प्रवीण कुमार घूमे, खजिनदार अशोक कुमार नाविक, उप खजिनदार अभिषेक सिंह, कप्तान एंटो पूथूर ,उप कप्तान ज्ञानेश्वर, पूर्व अध्यक्ष डॉ पुष्कर शिकारखाने ,संत राज गांगुली, आशीष ब्रह्मदिन यादव, डॉ जितेंद्र कर्णिक, पार्थ शैट्टी, कन्हैया धुरिया, कैलाश खंडागले, उमेश जैसवार, पाटा जैसवार, अरविंद राजभर, सुजीत विश्वकर्मा, मुख्तार अंसारी, शत्रुघ्न सिंह, विशाल गुप्ता, नरेंद्र महाडीक, अनुराग सिंह, गोविंद मेडवाल, विनोद जावीर, रवी कुमार राजभर, ध्रुव राज निषाद, द्वारकानाथ पाटिल, विकास सिंह, अब्दुल मुकीम, संदीप सोशटे,रोहित गुप्ता, जावेद शेख, राम यादव, इंद्रदेव यादव ,रुगल यादव, अर्जुन, गजानन टांडले इत्यादि शामिल हैं।

कामन में हनुमान जन्मोत्सव शोभायात्रा व कवि सम्मेलन सम्पन्न

वसई रोड। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर वसई पूर्व में भव्य शोभायात्रा व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। रविवार सुबह ११.०० बजे कोल्ही गांव के गांवदेवी मंदिर से रामभक्तों का विशाल जनसमूह भजन भाव के साथ भगवा ध्वज फहराते हुए सात किलोमीटर लंबे यात्रा पर मार्ग पर जयकारों की गूंज करते हुए कामन स्थित श्रीराम मंदिर पहूंचे जहां श्री राम सेवा समिति की ओर से महाप्रसाद के बाद कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित था। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता सदाशिव चतुवेर्दी ₹मधुर₹ ने किया तथा संचालन उमेश मिश्र प्रभाकर ने किया। युवा ओज कवि राजेश ₹अल्हड़ असरदार₹ के संयोजन में डॉ. मृदुल ₹महक₹, अन्नपूर्णा ₹सरगम₹ रामकृष्ण गुप्ता ने उपस्थित जनसमूह को कविताओं का रसपान कराया। अतिथियों में दिनेश म्हात्रे, जीत सिंह, सुनील मिश्रा, बाला सकपाल आदि राजनेताओं के साथ राम सेवा समिति के अध्यक्ष फूलचंद प्रजापति उपस्थित रहे। यात्रा का आयोजन सकल हिंदू समाज के प्रमोद मिश्रा, अश्विन कुमार, शिवम यादव, विमलेश दुबे, दिनेश विश्वकर्मा, निलेश दुबे, बिपिन पांडे, आकाश हजारे, राहुल दुबे, निशांत भुसाले व रतन पटेल द्वारा किया गया। सभी कवियों व अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। भीषण गर्मी में भी हजारों की संख्या में रामभक्त महिला पुरूष व बच्चों ने यात्रा में सहभाग लिया। सात किलोमीटर लंबे यात्रा मार्ग पर जगह जगह पर पानी व शरबत की व्यवस्था स्थानीय व्यवसायिकों ने व ग्राम वासियों ने किया था। राजेश दुबे ने सभी का आभार व्यक्त किया।

एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ने ग्रामीण विकास पहल के तहत 298 सीमावर्ती गांवों को कवर किया

पटना (उत्तरशक्ति)। भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक ने अपनी सीएसआर शाखा परिवर्तन के तहत देश भर में 298 सीमावर्ती गांवों को अपने ग्रामीण विकास पहल के तहत कवर किया है। गांवों के ये समूह बिहार,असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं। बैंक की योजना आने वाले वर्षों में 150 अतिरिक्त सीमावर्ती गांवों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की है। ये पहल केंद्र के बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में उल्लिखित राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं। इस पहल के बारे में बोलते हुए, एचडीएफसी बैंक के डीएमडी कैजाद भरूचा ने कहा, हम प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षा, बेहतर कृषि उत्पादकता, नवीकरणीय ऊर्जा और आजीविका के अवसरों तक पहुँच प्रदान करके भारत के सीमावर्ती गाँवों में सार्थक प्रभाव पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाकर, हम स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी निकायों के साथ मिलकर मजबूत, आत्मनिर्भर और जीवंत समुदाय बनाने के लिए सहयोग करते हैं जो भारत के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने में योगदान करते हैं। एचडीएफसी बैंक में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी प्रमुख नुसरत पठान ने कहा, ग्रामीण विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण न केवल वांछनीय है, बल्कि खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में अति आवश्यक है।

मुंबई की झोपड़पट्टी से लोकतंत्र के मंदिर तक : एक चौकीदार के बेटे की प्रेरणादायक यात्रा

नई दिल्ली। भारत के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की ताकत का जीता-जागता उदाहरण हैं अमरजीत सिंह, जिन्होंने मुंबई की झोपड़पट्टियों में पले-बढ़े होने के बावजूद राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम जैसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्हें यह प्रमाणपत्र भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हाथों नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में प्रदान किया गया।

अमरजीत की यह कहानी केवल एक व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, आशा और दृढ़ संकल्प की प्रतीक है। एक ऐसे परिवार में जन्मे जहां उनके पिता चौकीदार की नौकरी करते थे, अमरजीत ने बलिदान, कठिन परिश्रम, सामाजिक प्रतिबद्धता और लोकतांत्रिक मूल्यों में अडिग विश्वास के बल पर संसद तक की

यात्रा तय की। यह यात्रा आसान नहीं थी, अमरजीत कहते हैं, लेकिन भारत का संविधान अंतिम व्यक्ति को भी सपने देखने और उन्हें पूरा करने की ताकत देता है।

उनके ये शब्द पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉ. भीमराव आंबेडकर जी, और कांशीराम जी के उन सपनों की याद दिलाते हैं, जिन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां हाशिए पर खड़ा व्यक्ति भी संसद तक पहुंच सके।

एल.एस. रहेजा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स (मुंबई विश्वविद्यालय) से वाणिज्य में स्नातकोत्तर करने के बाद, उन्होंने भारतीय जनतांत्रिक नेतृत्व संस्थान (रंभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी) से राजनीति, नेतृत्व और सुशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी प्राप्त किया है। वर्तमान में वे सीए फाइनल की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही वे पिछले सात वर्षों से झुग्गी बस्तियों के गरीब छात्रों के लिये कार्य कर रहे हैं।

उनके प्रयासों से सैकड़ों बच्चों को शिक्षा, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की दिशा मिली है। मेरे लिए शिक्षा ही संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता बनी, और मैं चाहता हूं कि यही रास्ता दूसरों के लिए भी खुले, वे कहते हैं।

अमरजीत अपनी सफलता का श्रेय विश्व हिंदू परिषद के महाराष्ट्र-गोवा क्षेत्रीय प्रमुख नरेश पाटिल को देते हैं और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक और प्रेरणास्त्रोत मानते हैं। उनके शब्दों में, यह सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि भारत की बस्तियों में रहने वाले हर अनदेखे, अनसुने बच्चे की यात्रा है। आज मैं लोकतंत्र के मंदिर में एक दर्शक नहीं, बल्कि उम्मीद का प्रतिनिधि बनकर दाखिल हुआ हूं। निस्संदेह, अमरजीत की यह यात्रा भारतीय लोकतंत्र की गहराई और संविधान की शक्ति का प्रमाण है, जो हर अंतिम व्यक्ति को असंभव लगने वाले सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देता है।

गौरव स्वीट्स टाटा एस ईवी से बदल रहा है डिलीवरी का तरीका

ठाणे। ठाणे जैसे व्यस्त शहरों में, जहां गुणवत्ता और सुविधा की मांग दिनोंदिन बढ़ रही है, ताजा मिठाइयों का आनंद उठाना बहुत खास है। वर्ष 2006 से, गौरव स्वीट्स ने अपनी अलग पहचान बनाई है और यह अपनी 20 दुकानों में परंपरा और भरोसे के साथ मिठाइयों की बिक्री करता है। अब अपने कामकाज को और मजबूत करने के लिए, गौरव स्वीट्स ने टाटा मोटर्स के साथ मिलकर लगातार बढ़ रहे अपने गाड़ियों के समूह में इलेक्ट्रिक फोर-व्हील्ड छोटे कमर्शियल वाहनों को शामिल किया है।

गौरव स्वीट्स के संस्थापक और सीईओ गौरव पटेल कहते हैं, ₹हम हर कदम पर यही सोचते हैं कि अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा कैसे दें - न सिर्फ स्वाद में, बल्कि अनुभव में भी। पहले हमने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर से डिलीवरी शुरू की थी, लेकिन वे हमारी जरूरतों को पूरा

नहीं कर सके। फिर हमने एस ईवी को चुना जोकि हमारी यात्रा में एक महत?वपूर्ण फैसला था। इसने हमें डिलीवरी बढ़ाने का भरोसा दिया। यह गाड़ी बेहतर रेंज, शानदार राइड और बेहतर भरोसा देती है। और सबसे जरूरी, इसने हमें हर बार ताजा मिठाइयां समय पर पहुंचाने का वादा निभाने में मदद की। एस ईवी जैसे इलेक्ट्रिक ट्रक ने गौरव स्वीट्स को शहर की बढ़ती डिलीवरी जरूरतों को पूरा करने में बहुत मदद की है। यह उन्हें अच्छी गुणवत्ता बनाए रखने और तेज और स्वच्छता के साथ की जाने वाली डिलीवरी को अपनाने की ताकत देता है। यह ट्रक शहर की संकरी गलियों में आसानी से चलता है। एक बार चार्ज करने पर यह 154 किमी तक जाता है और इसका रखरखाव भी कम है, जिससे डिलीवरी बिना रुकावट चलती रहती है। डिलीवरी करने वालों के लिए इसका मतलब है कम देरी और सड़क पर ज्यादा भरोसा। गौरव स्वीट्स में नया करने का मतलब सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे भागना नहीं है। यह लोगों, अपने उद्देश्य और तरक्की के प्रति ईमानदार रहने की बात है। सही साधनों और स्पष्ट सोच के साथ, वे एक समय में एक मिठाई का डिब्बा और समझदारी भरे एक फैसले के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

टूक ने पेश किया गेमिंग सीरीज में बड्स क्रिस्टल डायनो

मुंबई। आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए विख्यात भारत के सबसे तेजी से विकसित होते ऑडियो ब्राण्ड्स में से एक टूक ने भारतीय मार्केट के लिए अपनी नई गेमिंग सीरीज के लॉन्च की घोषणा की है। बड्स क्रिस्टल डायनो स्लीक चार्जिंग केस, प्रीमियम लैदर फिनिश के साथ भव्य एवं टिकाउ है तथा स्टोरेज एवं चार्जिंग के लिए स्टाइलिश और व्यवहारिक भी है। नया बड्स क्रिस्टल डायनो 21 अप्रैल से एमजॉन डॉट इन, फ्लिपकार्ट और टूक डॉट इन पर रु 1099 की कीमत पर खरीद के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि शुरूआती उपभोक्ता मात्र रु 799 की स्पेशल कीमत पर इसे खरीद सकते हैं, यह ऑफर मात्र 2 घण्टे के लिए वैलिड होगा, जिसके बाद इसकी कीमत रु 999 होगी। तीन आकर्षक रंगों, रैवन ब्लैक, ओक ब्राउन एवं आर्कटिक ब्लू में उपलब्ध बड्स क्रिस्टल डायनो मेड इन इंडिया की अभिव्यक्ति करता है, तथा अपनी शानदार गुणवत्ता के साथ स्थानीय टेक निर्माण को समर्थन प्रदान करता है। लॉन्च के अवसर पर पंकज उपाध्याय, संस्थापक एवं सीईओ, टूक ने कहा, गेमिंग उद्योग लगातार दो अंकों की सालाना दर से विकसित हो रहा है, इसके बावजूद देश के कई टियर 2 और टियर 3 शहरों में प्रीमियम गेमिंग गियर सुलभ नहीं हैं। अपनी नई पेशकश बड्स क्रिस्टल डायनो के साथ हम उच्च गुणवत्ता के बजट अनुकूल ऑडियो समाधान के माध्यम से इस कमी को दूर कर युवा गेमर्स की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं।

ट्रक से कुचलकर एक परिवार के चार लोगो की मौत

प्रयागराज (उत्तरशक्ति)। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार, प्रयागराज के नैनी थाना इलाके में नए यमुना पुल के पास निमार्णाधीन रेलवे पावर हाउस के पास बुधवार तड़के 3:00 के पास के यहां पर गिट्टी लादकर चालक ट्रक लेकर पहुंचा। इसके दौरान ट्रक बैक करते समय तीन बच्चों के साथ मजदूर छोटेलाल (45) पुत्र देवशरण चपेट में आ गए। हादसे में चारों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक शंकरगढ़ थाना इलाके के कपारी गांव का रहने वाला था।

हिसर पुलिस ने फरियादियो को 54 लाख के सोना, चांदी, नगद, मोबाइल और लेपटॉप लौटाया

मुंबई (उत्तरशक्ति)। मुंबई के दहिसर पूर्व स्थित दहिसर पुलिस ने मुख्यमंत्री द्वारा 100 दिन के कार्यक्रम के साथ पुराने केसों में जमा मुद्देमाल फरियादियो को वापस किया गया। आरोपियों के पास से बरामद 54 लाख 20 हजार 460 रुपये का जेवर, मोबाइल, लैपटॉप, नगद को स्मिता पाटिल पुलिस उपायुक्त परिमंडल 12 के मार्गदर्शन में पुलिस ने फरियादियो को वापस लौटाया है। स्मिता पाटिल पुलिस उपायुक्त परिमंडल 12 ने बताया कि दहिसर पुलिस स्टेशन में दर्ज आपराधिक एवं सायबर मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में डिटेक्शन टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से जांच पड़ताल के दौरान 296.88 ग्राम सोना,51.05 ग्राम चांदी, नगद, 61 मोबाइल फोन, 08 लैपटॉप सहित कुल 54 लाख, 20 हजार, 460 रुपए का माल समान जप्त किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आदेशानुसार 100 दिनों के अंतर्गत शिकायतकर्ता एवं मूल मालिको को पुलिस स्टेशन में बुलाकर सभी मालमत्ता को वापस लौटने का कार्य दहिसर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक होंनमाने ने डीसीपी स्मिता पाटिल, सहायक पुलिस आयुक्त किशोर खैरनार एवं अन्य पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में लौटाया गया। उम्मीद खो चुके फरियादियो को चोरी गया समान एवं मोबाइल वापस मिलने पर काफी खुशनजर आए साथ ही पुलिस का आभार प्रकट किया।

दो साल बाद दिल्ली का 48वां इंडिया कारपेट एक्सपो सबसे सफल मेला : कुलदीप राज वट्टल

-सुरेश गांधी

वाराणसी। भारत मंडपम, नई दिल्ली के हाल नंबर एक में कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित इंडिया कारपेट एक्सपो दो साल बाद अब तक सबसे सफल कालीन मेला साबित हुआ है। 48वें एक्सपो के तीन दिनों में 45 देशो से 215 विदेशी खरीदारों और 140 खरीद प्रतिनिधियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। यह बातें सीईपीसी के चेयरमैन कुलदीप राज वट्टल ने कहीं। उन्होंने कहा कि मेले में भाग लेने वाले सभी जनप्रतिनिधियों ने कारपेट इंडस्ट्री को भरपूर सहयोग का वादा किया है।

उन्होंने बताया कि कालीन मेले में विजिट के दौरान सांसद एवं राज्यसभा सदस्य अरुण कुमार सिंह, एमएसएमई, खादी, ग्रामोद्योग, रेशम उत्पादन, कपड़ा मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार एवं कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय विभाग उप्र कैबिनेट मंत्री

अनिल राजभर से मांग की गयी है कि इंटरेस्ट इक्वालिजेशन स्कीम के लिए समय और बढ़ा दिया जाय। इसके अलावा कम से कम 5 फीसदी सब्सिडी दिया जाय। 43 बीएच के तहत एमएसएमई में पेमेंट भुगतान के समय को 45 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया जाय, क्योंकि कालीन एक लघु कुटीर उद्योग है। जिसमें एक कालीन को तैयार करने में काफी समय लगता है। मंत्री ने आश्वाशन दिया है कि उपरोक्त विषय पर सरकार से बात करके पूरा सहयोग करने की कोशिश की जाएगी।

सीईपीसी के अध्यक्ष कुलदीप राज वट्टल ने बताया कि भारत मंडपम, नई दिल्ली के हाल नंबर एक में कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित इंडिया कारपेट एक्सपो के 48वें संस्करण के तीन दिनों में दुनिया भर से लगभग 215 विदेशी खरीदारों और 140 खरीद प्रतिनिधियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने मेले में भाग लिए सभी सभी निर्यातको को उनकी भागीदारी और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया, जिन्होंने अपने नवीनतम डिजाइन, रंग विरंगी उत्पाद प्रदर्शित किए, जिसने विदेशी खरीदारों को आकर्षित किया. उन्होंने बताया की आज तीसरे दिन मेले में काफी अयाताको ने निर्यात आर्डर दिए, बीते तीन दिनों में अनेक आयातक और उनके प्रतिनिधिओ मेले में आये और निर्यात व्यापार किया।

कुलदीप राज वट्टल ने बताया कि प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया के अनुसार, खरीदारों ने लगभग सभी प्रदर्शकों के स्टालों का दौरा किया और व्यापार वार्ता प्रक्रियाधीन है, और उम्मीद जताया कि इस बार अच्छा व्यवसाय उत्पन्न होगा। इस अवसर पर अध्यक्ष कुलदीप राज वट्टल और सीईपीसी के प्रशासनिक समिति सदस्य अनिल कुमार सिंह, वासिफ अंसारी, असलम महबूब, इम्तियाज अहमद, रोहित गुप्ता, पियूष बरनवाल, हुसैन जफर हुसैनी, संजय गुप्ता, शेख आशिक अहमद, महावीर प्रताप शर्मा, बोधराज मल्होत्रा, दीपक खन्ना, मेहराज यासीन, कैप्शन मुकेश कुमार गोबर, शौकत खान तथा डाक्टर स्मिता नागरकोटी अधिशासी निदेशक सचिव, सीईपीसी सहित सभी लोग इस एक्सपो से काफी आश्वस्त है।

पुलिस ने गैर जनपद से भटकी विक्षिप्त महिला को उसके परिजनो को किया सुपुर्द

जौनपुर(उत्तरशक्ति)। थाना महराजगंज पुलिस द्वारा गैर जनपद से भटकी हुई विक्षिप्त हालत में मिली महिला के परिजनो का पता लगाकर किया गया सुपुर्द।पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा जनपद मे अपराध की रोकथाम एवं महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने सम्बन्धी चलाए जा रहे के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, शैलेन्द्र सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी बदलापुर जौनपुर, विवेक सिंह के पर्वेक्षण में थाना महराजगंज पुलिस द्वारा गैर जनपद से भटही हुई विक्षिप्त हालत में मिली महिला के बाबत संजीदगी से संज्ञान लेते हुए आस पास के थानो व जनपदो में प्रयास कर उसके परिजनो तक पहुँचाया गया जिस क्रम में ज्ञात हुआ कि संगीता देवी पत्नी धर्मेन्द्र कुमार निवासी उसरौली थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ है जो विक्षिप्त हालत में दिनांक-14.04.2025 को अपने घर ग्राम उसरौली थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ से बिना किसी को बताये भटकते हुए महराजगंज थाना क्षेत्र में आ गयी थी जिसे 112 की पुलिस टीम द्वारा थाना हाजा पर संज्ञानित कराया गया अथक परिश्रम के बाद ज्ञात हुआ कि उक्त महिला धर्मेन्द्र कुमार पुत्र राम खेलावन ग्राम उसरौली थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ की पत्नी है सूचना देकर धर्मेन्द्र कुमार व उनके अन्य परिजनों थाना हाजा पर उपस्थित आये व संगीता उपरोक्त को अपने परिवार के सदस्यों के रुप में पहचान किये जिनके आधार कार्ड प्राप्त कर पूर्णरुप से पहचान कराकर तस्दीक होने के बाद उनकी सुपुर्दी मे दिया गया।

चिंचोटी-भिंवाड़ी राजमार्ग का 'शुक्ल काष्ठा' हटाया जाएगा

वसई रोड। चिंचोटी-कामन-भिवंडी सड़क के लंबे समय से लंबित कार्य को निपटाने के लिए आज मंत्रालय में लोक निर्माण मंत्री और लोक निर्माण विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक वसई विधायक स्नेहा दुबे पंडित के साथ हुई। जिसमें भिवंडी तालुका में चिंचोटी-कामन-भिवंडी सड़क, जो वसई तालुका को जोड़ती है, बहुत खराब स्थिति में है और वसई-विरार क्षेत्र के कर्मचारियों, श्रमिकों और उद्यमियों को काम के लिए इस सड़क पर दैनिक आवागमन के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वसई के विधायक चुने जाने के बाद स्नेहा दुबे ने नागपुर में विधानसभा के पहले शीतकालीन सत्र में इस सड़क का मुद्दा उठाया गया था। बाद में उन्होंने बजट सत्र में इस मुद्दे को फिर उठाया। इस संबंध में राज्य के लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले @ छत्रपतिशिवेंद्रसिंहराजे ने आज मंत्रालय में बैठक आयोजित की। इस बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अधिकारीगण, जिनमें मैं भी उपस्थित थे। इस समय इस सड़क की खस्ता हालत के कारण नागरिकों की दुर्दशा, मा. मंत्री के ध्यान में लाया गया। उन्होंने मांग की कि इस सड़क की मरम्मत का काम तुरंत शुरू किया जाए। माननीय मंत्री ने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद इस सड़क पर रुके हुए कार्य को शीघ्र शुरू किया जाएगा। मंत्री ने आश्वासन दिया।

वसई विरार नगर निगम के अभ्यासिका के छात्रों ने विधायक राजन नाइक का किया धन्यवाद

-नरेन्द्र सोनी

नालासोपारा। नालासोपारा पूर्व मजेठिया में अध्ययन कक्ष में समस्याओं को लेकर छात्रों की शिकायत पर विधायक राजन नाइक ने तत्काल दौरा किया और कमिश्नर से बात किया। जिस पर कमिश्नर ने शीघ्र ठीक करने का आश्वासन दिया। बता दे कि वसई विरार शहर महानगरपालिका विभिन्न विभागों में पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष चला रही है। उनमें से नालासोपारा के पूर्व आचोले क्षेत्र में मजेठिया परिसर में अव्यवस्था को लेकर वहां के विद्यार्थियों ने नालासोपारा के विधायक राजन नाइक को ज्ञापन सौंपकर अव्यवस्था में सुधार लाने का अनुरोध किया। विधायक नाईक ने तत्काल छात्र से मुलाकात की। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश का भविष्य कहलाने वाले छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। विधायक को अध्ययन कक्ष में देखकर उपस्थित विद्यार्थियों के मन में खुशी की लहर दौड़ गई, तो विद्यार्थियों ने भी विधायक के समक्ष खुलकर अपना दुखड़ा सुनाया। विधायक ने विद्यार्थियों के साथ मिलकर पूरे अध्ययन कक्ष का भी निरीक्षण किया। जहां यह पाया गया कि द्वितीय तल पर स्थित हॉल में टूटी हुई कुर्सियां, पंखे और एसी, अशुद्ध जल देने वाले वाटर फिल्टर की खराब स्थिति और शौचालयों की बहुत खराब और अस्वच्छ स्थिति के बावजूद मासिक शुल्क में वृद्धि की गई। विद्यार्थियों की इस असुविधा का तत्काल समाधान करने के लिए विधायक नाईक ने वसई विरार शहर महानगरपालिका आयुक्त अनिल पवार से फोन पर बात की तथा पूरा मामला उनके ध्यान में लाया। आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि बढ़ी हुई फीस तुरंत रद्द कर दी जाएगी तथा सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। उन्होंने छात्रों के बयान पर तत्काल संज्ञान लेने के लिए विधायक को धन्यवाद दिया।

वाराणसी के डीएम ने सुनी जनता की फरियाद, अफसरों को दिए कड़े निर्देश

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद के जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे और अपनी शिकायतें जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। जनता की बातों को गंभीरता से सुनते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता की और समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप और पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। एस. राजलिंगम ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जन समस्याओं के प्रति लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि शिकायतकर्ता को समय पर न्याय और समाधान मिले। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे आमजन सीधे प्रशासन से संवाद कर सकते हैं। इसलिए इसकी प्रक्रिया को गंभीरता और संवेदनशीलता से अपनाना आवश्यक है।

चौबेपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा गैंगस्टर, पहले से दर्ज हैं पांच मुकदमे, काफी दिनों से थी तलाश

वाराणसी(उत्तरशक्ति)। जनपद के चौबेपुर पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। सटीक सूचना के आधार पर दबिश देकर उसके गांव उगापुर में दबिश देकर पकड़ा। आरोपित के खिलाफ पहले से पांच मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस काफी दिनों से उसकी तलाश कर रही थी।थाना चौबेपुर से संबंधित मु.अ.सं. 0237/2025 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत वांछित आरोपी मुलायम यादव पुत्र लालबहादुर यादव, निवासी ग्राम उगापुर, थाना चौबेपुर की पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। बुधवार को पुलिस को सूचना मिली कि गैंगस्टर अपने गांव में मौजूद है। इस पर पुलिस ने दबिश देकर उसे पकड़ लिया।मुलायम का लंबा अपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अलावा भा.दं.वि. की धाराओं 323, 504, 506, आर्म्स एक्ट तथा बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत कुल पांच मुकदमे दर्ज हैं।

इजराइल का गाजा में नई रणनीति का ऐलान, कहा- 'सुरक्षा क्षेत्रों' से कभी नहीं हटेंगे हमारे सैनिक

इजराइल। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने स्पष्ट किया है कि इजराइली सेना गाजा पट्टी के तथाकथित 'सुरक्षा क्षेत्रों' में अनिश्चित काल तक बनी रहेगी। बुधवार को दिए गए एक बयान में कैट्ज ने कहा कि सेना ग्गाजा में किसी भी अस्थायी या स्थायी स्थिति में दुश्मन और इजराइली समुदायों के बीच सुरक्षा प्रदान करने के लिए ढाल के रूप में तैनात रहेगी। इजराइल ने गाजा के अंदर कुछ सीमावर्ती इलाकों को 'सुरक्षा क्षेत्र' घोषित किया है, जो गाजा और इजराइल की सीमा के नजदीक स्थित हैं। यहां पर सेना की स्थायी उपस्थिति का उद्देश्य हमास और अन्य आतंकवादी समूहों से संभावित खतरे को रोकना है। यह पहला मौका है जब इजराइल ने खुले तौर पर कहा है कि सेना गाजा में अनिश्चितकाल तक रहेगी। यह युद्ध के बाद की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। कैट्ज का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल पर युद्धविराम और मानवीय राहत की अपीलें बढ़ रही हैं। इजराइली रक्षा नीति में बदलाव यह संकेत देता है कि गाजा पर भविष्य में भी इजराइली प्रभाव बना रह सकता है, भले ही युद्ध समाप्त हो जाए। गाजा में पिछले छह महीनों से चल रही जंग में हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों विस्थापित हुए हैं।संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने इजराइल से तत्काल युद्धविराम की अपील की है, लेकिन इजराइली सरकार फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है।

नेपाल में विमान की आपात लैंडिंग!

काठमांडु। एक विमान को उसकी ह्यहाइड्रोलिक' प्रणाली में खराबी आने के बाद आपात स्थिति में काठमांडू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा, जिसमें 12 भारतीय भी सवार थे। एयरलाइन के एक अधिकारी ने बताया कि माउंट एवरेस्ट क्षेत्र के प्रवेशद्वार लुक्ला से रामेछाप जा रहे निजी कंपनी ह्यसीता एयर' के विमान में तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद उसे त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया। अधिकारी ने बताया कि डोर्नियर विमान में 12 भारतीय, दो नेपाली और चालक दल के तीन सदस्य सवार थे। विमान के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उसे ट्रैक्टर की मदद से पार्किंग स्थल तक ले जाया गया। अधिकारी ने बताया इस विमान में हाइड्रोलिक प्रेशर" में कमी का संकेत मिला। विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चकबन्दी विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में चकबन्दी विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जनपद में कुल 97 ग्राम वर्तमान में चकबन्दी प्रकिया के अन्तर्गत हैं। अभी तक जनपद में चकबन्दी हेतु नव प्रसारित ग्रामों में से 06 ग्रामों में तरमीम का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, 02 ग्राम दिलशादपुर व नारायणपुर का धारा-9 पूर्ण कर लिया गया है तथा 02 ग्रामों का धारा 9 माह अप्रैल 2025 में पूर्ण कर लिया जायेगा। नवप्रसारित ग्रामों में मानक के अनुसार तरमीम एवं पड़ताल का कार्य पूर्ण कराने तथा जिन ग्रामों में चकबन्दी प्रकिया का विरोध है वहां पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के साथ खुली बैठक कराके ग्राम की चकबन्दी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को दिये गयें। इसके अतिरिक्त 10 वर्ष से अधिक पुराने ग्रामों मे भी शासन एवं चकबन्दी आयुक्त के निदेर्शानुसार कार्ययोजना बनाकर ग्राम की चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में सम्मिलित विषय के अनुसार उपसंचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी व चकबन्दी अधिकारी न्यायालयों में 05 वर्ष से अधिक पुराने वादों का शत-प्रतिशत निस्तारण कराने के निर्देश दिये गयें हैं। धारा-9 के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण ग्राम अदालत के माध्यम से सुनिश्चित करने के निर्देश सभी चकबन्दी अधिकारियों को दिये गयें। तहसील केराकत के नव प्रसारित चकबन्दी ग्रामों के भूचित्र अभिलेखागार से अविलम्ब ट्रेस कराकर ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया आगे बढ़ाने हेतु सम्बन्धित चकबन्दी अधिकारी व सहायक चकबन्दी अधिकारी को निर्देशित किया गया बैठक में अपर जिलाधिकारी (भू०रा०) अजय अंबष्ट, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी अशोक कुमार, सहित चकबन्दी अधिकारी किरतापुर एवं जनपद के समस्त सहायक चकबन्दी अधिकारी व चकबन्दीकर्ता उपस्थित रहे।

भारतीय समेत 4 विदेशी छात्रों ने ट्रंप प्रशासन पर ठोका मुकदमा, इमिग्रेशन स्टेटस रद्द करने को दी चुनौती

नई दिल्ली। अमेरिका में पढ़ रहे एक भारतीय और तीन अन्य विदेशी छात्रों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कराया है। इन छात्रों का कहना है कि बिना किसी जानकारी या वजह के उनका स्टूडेंट वीजा और इमिग्रेशन स्टेटस खत्म कर दिया गया, जिससे उन्हें देश छोड़ने को कहा गया। भारतीय छात्र चिन्मय देवरे, चीन के जियांगयुन बु और क्यूई यांग, और नेपाल के योगेश जोशी अमेरिका के वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। इन सभी ने अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी और इमिग्रेशन अधिकारियों के खिलाफ केस किया है। छात्रों ने कहा कि वे न तो किसी प्रदर्शन में शामिल थे, न ही उन्होंने कोई कानून तोड़ा है, लेकिन फिर भी बिना जानकारी दिए उन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। अब वे कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि उनका लीगल स्टेटस फिर से बहाल किया जाए। यह मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब ट्रंप प्रशासन लगातार विदेशी छात्रों के वीजा रद्द कर रहा है। छोटी-मोटी गलती या कानून के मामूली उल्लंघन पर भी छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। मिशिगन की अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने इन छात्रों की तरफ से कोर्ट में केस दाखिल किया है। अउछव ने कहा कि ट्रंप सरकार का मकसद डर फैलाना है और वह विदेशी छात्रों को निशाना बना रही है, जो अमेरिका की शिक्षा और अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं। कुछ दिन पहले एक और भारतीय छात्र कृष लाल इस्सरदासानी को भी डिपोर्ट करने का आदेश दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक लगा दी है।

कश्मीरी पंडितों का 35 वर्षों का इंतजार, घाटी जाने की आस

जम्मू। कश्मीर घाटी आखिरकार एक निर्बाध रेलवे लाइन के माध्यम से शेष भारत से भौतिक रूप से जुड़ने के लिए तैयार है, जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधान मंत्री द्वारा किया जाएगा। यह लंबे समय से प्रतीक्षित लिंक सुलभता, विकास और राष्ट्रीय एकीकरण के एक नए युग की शुरूआत है। फिर भी, जब राष्ट्र इस मील के पत्थर का जश्न मना रहा है, तो विस्थापित कश्मीरी पंडित (के.पी.) समुदाय के बीच एक मार्मिक प्रश्न गूंज रहा है कि वे भी अपनी मातृभूमि से स्थायी रूप से कब जुड़ेंगे? दशकों से, वे न केवल बुनियादी ढांचे के लिए, बल्कि अपनेपन, सम्मान और न्याय की भावना के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को अभी भी अपनी मातृभूमि से स्थायी रूप से जुड़ने इंतजार है। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय के. टिक्कू ने पंजाब केसरी को बताया कि पिछले 35 वर्षों से कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास अभी तक बयानबाजी ही बना हुआ है, चुनावों के दौरान राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। कश्मीरी पंडितों के लिए एक वास्तविक पुनर्वास नीति बनाने पर विधानसभा में हाल ही में चर्चा हुई। ऐसी चर्चाएं अक्सर वास्तविक कार्रवाई में तबदील हुए बिना विधान मंडलों तक ही सीमित रह जाती हैं। कश्मीरी पंडितों को 1990 की त्रासदी अभी तक नहीं भूली है। के.पी. सिर्फ यादों तक सीमित रह गए हैं, जो एक ऐसे घर की लालसा कर रहे हैं जिसे वे अब अपना नहीं कह सकते। टिक्कू ने कहा कि समुदाय के कई लोग, खास तौर पर युवा, कश्मीर से बाहर चले गए हैं। समय के साथ उनका जमीन से जुड़ाव कमजोर होता जा रहा है। अगर कोई नीति सिर्फ अस्तित्व से ज्यादा कुछ नहीं देती है, तो उन्हें वापस लौटने के लिए कैसे मनाया जाएगा। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के माध्यम से भारत के गृह मंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें अगले 60 दिनों के भीतर एक ठोस पुनर्वास रोडमैप की मांग की गई है। टिक्कू ने कहा कि निर्वासन का रास्ता बहुत लंबा हो गया है। अब समय आ गया है कि भारत सरकार यह साबित करे कि कश्मीरी पंडित सिर्फ चुनावी घोषणापत्रों में एक भूला हुआ फुटनोट नहीं हैं, बल्कि अपनी मातृभूमि के असली उत्तराधिकारी हैं।

सवारियों से भरी मैटाडोर के साथ घटा भयानक हादसा, मौके पर मच गई चीख-पुकार

सांबा। सांबा मानसर मार्ग पर बुधवार को एक मैटाडोर और ट्राले की टक्कर में आधा दर्जन सवारियां मामूली रूप से घायल हो गई। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल सांबा में पहुंचाया गया है। जानकारी के अनुसार मैटाडोर सांबा से बट्टल की तरफ सवारियां लेकर जा रही थी। इस दौरान जब गाड़ी मानसर मार्ग पर पापड़ मोड़ के आगे पहुंची तो कश्मीर से आ रहे एक कैंटर ने टर्न करने की बजाए सीधे मैटाडोर के सामने टक्कर मार दी। इस हादसे में मैटाडोर में बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में मैटाडोर का फ्रंट शीशा पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर होकर सवारियों पर जा गिरा। इस हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे लोगों ने उन्हें एंबुलेंस में जिला अस्पताल सांबा में उपचार के लिए भेजा। वहीं मैटाडोर के चालक ने बताया कि ट्राले को देखकर उसने पुल के ऊपर पहले ही गाड़ी रोक दी थी, लेकिन कैंटर चालक से ब्रेक नहीं लग पाई और उसने सीधा सामने टक्कर मार दी। वहीं मानसर पुलिस चौकी, नड नाके और ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को देखा। मानसर पुलिस चौकी टीम ने मामला दर्ज करके कारवाई शुरू कर दी है। हादसे में गंभीर घायल महिला की पहचान बिमला देवी निवासी सुंब दनेई के रूप में की गई है।

नहीं रुक रहा है सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा

सिरकोनी,जौनपुर(उत्तरशक्ति)। स्थानीय विकास खण्ड क्षेत्र के सेहमलपुर गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। गाटा संख्या 1858 पर छोटे लाल पुत्र तपेसरी द्वारा अनधिकृत रूप से चहारदीवारी और मकान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह भूमि नवीन परती खाते की है और अनुसूचित जाति की बस्ती के पास स्थित है। भूमि पर दावा है कि लेखपाल ने उन्हें मकान बनाने की अनुमति दी है। स्थानीय निवासियों ने इस दावे को खारिज कर दिया है। इसके पहले भी छोटे लाल ने इस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया था। स्थानीय लोगों की शिकायत पर लेखपाल ने धारा 67 राज्य संहिता 2006 के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। अब छोटे लाल 0.36 हेक्टेयर क्षेत्र पर अवैध निर्माण का प्रयास कर रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि विरोध करने पर छोटेलाल उन्हें धमकी देता है और दुर्व्यवहार करता है। उनका कहना है कि लेखपाल और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मदद से सरकारी जमीन पर कब्जा कराया जा रहा है। उच्चाधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है।